

[Shri N. Sreekantan Nair]

members should at least be allowed to make out what they mean by their amendments. So, more time should be allotted for this Bill, if it is going to be taken up and discussed.

## RE. MOTION FOR ADJOURNMENT

**Shri Hem Barua** (Mangaldai): After you have heard Mr. Nath Pai and the other members of this House, I think the best course open for you is to allow the adjournment motion.

**Mr. Speaker:** He can also allow it on my behalf.

**Shri Hem Barua:** I was making a humble submission to you. But you are saying.....

**Mr. Speaker:** Leave it to me. If he has suggested, I have heard him. I have heard patiently all the members; I have not objected to anybody.

## RE. ANNUAL REPORT OF THE INDIAN CENTRAL OILSEEDS COMMITTEE, FOR 1965-66

**Shri Ranga** (Srikakulam): I am sorry, I am going back to item 8 of the agenda paper, about papers laid on the Table. You will kindly see, Sir, that all these Reports are long overdue. Let them not make that mistake once again. Mr. Kamath used to draw attention to these things. They do not seem to have become any the wiser.

**Mr. Speaker:** Mr. Fakhruddin Ali Ahmed.

**An hon. Member:** What is your ruling?

**Mr. Speaker:** There is no ruling. There is no point of order.

**Shri Nath Pai** (Rajapur): What has happened to the adjournment motion?

**Shri Hem Barua** (Mangaldai): You should enlighten us about the position of the adjournment motion.

**Shri Nath Pai:** Is it pending?

12.42 hrs.

## PUBLIC WAKFS (EXTENSION OF LIMITATION) AMENDMENT BILL\*

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs** (Shri F.A. Ahmed): I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act, 1959.

**Mr. Speaker:** The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act, 1959."

*The motion was adopted.*

**Shri F. A. Ahmed:** I introduce the Bill.

12.42-1/2 hrs.

## MOTION RE. FOURTEENTH AND FIFTEENTH REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES FOR 1964-65 AND 1965-66—contd.

**Mr. Speaker:** We had allotted seven hours for the discussion of the Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, but we have already taken seven hours and twenty minutes. May I now request the Minister to reply?

श्री हुकम चन्द कश्यप : (उज्जैन)  
अध्यक्ष महोदय, इस पर दो घंटे का समय बढ़ाया जाये।

\*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 8-8-67.

**The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh):** We have suggested that one more hour be given for this motion.

**Mr. Speaker:** One more hour is already given. Seven hours were allotted, but we have already taken seven hours and twenty minutes and I am sure that the Minister will take about 40 minutes.....

**The Minister of Planning, Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta):** I have told the Deputy-Speaker that I would take 20 to 25 minutes.

**Mr. Speaker:** All right. Then two or three more members can speak. The Minister will reply at 2 O' Clock.

12.43½ hrs.

RE: MOTION FOR ADJOURNMENT  
(Query)

**Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara):** Am I to understand that you have not given any decision about the adjournment motion?

**Mr. Speaker:** I do not give here at all. I may allow or disallow. But on the floor of the House I am not going to say anything. I wish I had been convinced about it inside my Chamber, so that there could have been some argument; I could have argued the case inside the Chamber..... (Interruptions). The same thing happened about Neiveli strike notice and all that. I discussed and asked them: if every threatened notice of strike is given as an adjournment motion, what would happen. The same thing happened about Ranchi also. I have to convince myself by talking about it in the Chamber; on the floor of the

House I cannot do it. Unfortunately I cannot place my views here. If I do, it will become a debating table I will not be able to argue.

**Shri Surendranath Dwivedy:** We shall discuss the matter with you.

**Shri Hem Barua (Mangaldai):** When we came to your Chamber this morning, you were not there; you were late.

12.44½ hrs.

MOTION RE. FOURTEENTH AND FIFTEENTH REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES FOR 1964-65 AND 1965-66—contd.

**Mr. Speaker:** Mr. Sadhu Ram.

**श्री साधुराम (फिल्लोर):** अध्यक्ष महोदय, शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट्स जो कि हाउस के सामने पेश हैं उन के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं और मैं आप का शुक्रगुजार हूँ कि आप ने मुझे भी उस पर बोलने का थोड़ा समय दिया।

सन् 1961 की मर्दमशुमारो के हिसाब से सैशस के हिसाब से हमारे भाई कोई 20, 22 करोड़ के करीब बैठते हैं। 5 करोड़ के लगभग शैड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और 10 करोड़ शैड्यूल्ड कास्ट्स हैं और 5 करोड़ भदर बैकवर्ड क्लासेज हैं इस देश में ऐसे आदमी हैं जिनके साथ अभी तक इंसानियत का सलूक नहीं होता है। शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोग जंगलों में रहते हैं, या शहरों में रहते हैं उन को आदमियत का दर्जा नहीं मिलता है। इसलिए आजादी आने के बाद उन के लिए जो सीटें रिजर्व की थीं प्रेसेम्बलियों में और पार्लियामेंट में सीटें रिजर्व करने के बाद उन के नुमायन्दे जो आते हैं वह इसलिए भेजे गये कि यह

[श्री साधुराम]

पिछड़े हुए लोगों को कुछ नुमायन्दगी मिले और वह अपने उन गरीब भाइयों को जिनको कि हजारों सालों से गुलाम रक्खा गया है इस देश में उन के लिए कुछ काम कर सकें और आने वाले समय में उन को इंसानियत का दर्जा दिलाने के लिए वह अपनी जदोजहद करें। इसलिए उन्हें नुमायन्दगी दो गई थी आजादी आने के बाद उन लोगों की और उस की वजह से शैड्यूल ट्राइब्स और शैड्यूल कास्ट्स के लोग रिजर्व सीटों पर कामयाब होकर आते हैं। मगर इन सीटों पर कामयाब हो जाने के बाद पार्लियामेंट में या किसी असेम्बली में उन की आवाज को सुना नहीं जाता है। गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है तो इस का मतलब यह हो जाता है कि उन का प्रतिनिधित्व करने का कोई सवाल सामने नहीं रखते हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि लोक सभा में टोटल हरिजन मेम्बर 107 हैं जिन में से 76 रिजर्व सीटें शैड्यूल कास्ट की हैं 39 शैड्यूल ट्राइब्स की हैं। गवर्नमेंट बैंच के ऊपर 47 शैड्यूल कास्ट्स के और 19 मेम्बर्स शैड्यूल ट्राइब्स के बैठे हुए हैं। इस का मतलब यह हो गया कि 66 मेम्बर्स इस वक्त गवर्नमेंट बैंच पर हैं और 107 में से बाक़ी के मेम्बर्स असोजोशन में है। मेम्बर्स शैड्यूल कास्ट्स और शैड्यूल ट्राइब्स के यहाँ रिजर्व सीटों पर आये हुए हैं इस पार्लियामेंट में तो मतलब यह बनता है कि एक चौथाई 508 टोटल पार्लियामेंटरी सीटों में से 107-108 हैं। इस का मतलब यह बनता है कि पाँचवाँ हिस्सा इस देश के यह लोग हैं और जो रिजर्वेशन होता है वह पापुलेशन के हिसाब से होता है। इसलिए पाँचवे हिस्से के लोग इस देश के जो तक्रुरीबन पाँचवे हिस्से से कुछ थोड़े से ज्यादा हैं क्योंकि सेंशस में कुछ लोगों ने शलतियाँ की हैं। पिछली दफ़े में मध्य प्रदेश में हम ने इस बात की अपील की थी कि शैड्यूल कास्ट लोगों को सेंशस में जितनी असली पापुलेशन थी उस से कम दिखाई गई थी। मैं यह समझता हूँ कि देश में

जो बाक़ी लोग हैं उन के अलावा वह सारे के सारे अपना कुछ न कुछ धंधा करते हैं काम करते हैं। वह बेचारे गरीब लोग जिनके कि पास जमीन नहीं जिनके कि पास दुकान नहीं, जिनके पास मकान नहीं, जिनके पास कुछ चीज़ नहीं, उन का धंधा तो एक ही है कि वह यह बच्चों का प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं, औरों की अपेक्षा हमारे भाई बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। कोई इंडस्ट्री में तरक्की करता है और अन्य चीज़ों में तरक्की करता है लेकिन यह हरिजन लोग जैसा मैं ने कहा पापुलेशन बढ़ाने में ज्यादा तरक्की करते हैं। अगर कोई लोग यह कहें कि हम ने हिन्दुस्तान की आबादी को बढ़ाया है शैड्यूल कास्ट्स और शैड्यूल ट्राइब्स के लोगों ने नहीं बढ़ाया है तो मैं उस को क़तई शलत मानता हूँ। हिन्दुस्तान की आबादी के हिसाब से जैसे इस देश की आबादी बढ़ी है उस हिसाब से अगर देखा जाय तो हिन्दुस्तान में इस वक्त शैड्यूल कास्ट्स और शैड्यूल ट्राइब्स की आबादी 15 करोड़ से किसी तरह से कम नहीं है। 15 करोड़ की आबादी में यह अदर बैंकवर्ड क्लास जमा कर लिये जायें तो मेरा खयाल है कि वह करीब 20-22 करोड़ के जाकर बैठते हैं जिन पर कि जुल्म किया गया, जिन्हें कि दबा कर रक्खा गया और जिनको कि इंसानियत का दर्जा आज तक नहीं मिला है। 20 साल की आजादी आ जाने के बाद 20 साल हमारी गवर्नमेंट बन जाने के बाद शैड्यूल कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्ट यह साबित करती है और 47 पेज पर बतलाया गया है कि आज तक उनके साथ क्या सलूक हो रहा है कितनी छुआछूत और अनटचेबिलिटी हूटी है? इसने साबित कर दिया है कि यह बिलकुल 1 परसेंट, आधा परसेंट भी यह छुआछूत व अनटचेबिलिटी जो सवर्ण हिन्दू व अन्य दूसरे भाई अभी तक उनके साथ बर्तते रहे हैं वह अनटचेबिलिटी दूर नहीं हुई है।

इसकी मिसाल इस किताब से मिल जाती है। मैं बहुत लम्बी तकरीर नहीं करना चाहता क्योंकि हाउस के पास बहुत थोड़ा टाइम है और मुझे बहुत से प्वाइंटस अर्ज करने हैं। शैड्यूल्ड कास्टस कमिश्नर की रिपोर्ट इस बात को साबित करती है कि अभी इस देश में छुआछूत बहुत है। वह यहां तक है कि कोई शैड्यूल्ड कास्टस का आदमी धोती पहन कर किसी गांव में नहीं जा सकता, जूता पहन कर वह बाजार से नहीं गुजर सकता, किसी कुएं से पानी नहीं ले सकता, स्कूलों में उन के बच्चों को अलग बिठाया जाता है और उन से बैंगार ली जाती है। कब्रिस्तान में मुर्दे ले जाने के लिये भी उनसे बैंगार ली जाती है। ऐसी कई मिसाल हैं कि शर्म आती है कि आजादी आ जाने के बाद इस देश में यह हाल है। अगर यही हाल रहना है तो आजादी आने से कुछ नहीं होता है। 15-20 करोड़ आदमियों को इस तरह से दबा कर, इन्सानियत से बुरी दशा में उन्हे रखा जाये, यह हमारे लिये शर्म की बात है।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी इस बात में और ज्यादा बढ़ है क्योंकि हम गवर्नमेंट की तरफ बैठे हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट को दूसरों लोगों का क्लिटसाइज करना, उस पर एतराज करना, जायज है, लेकिन हम भी अपनी गवर्नमेंट को आगाह करना चाहते हैं कि पता नहीं वह किस स्वप्न में रहती है कि उसको 20 करोड़ आदमियों की खबर नहीं है कि उन लोगों की हालत क्या है और पहनने को कपड़ा नहीं है। अगर आप हरिजन वस्तियों में जाये तो आप को मालूम पड़ेगा कि उन के रहने के लिये मकान नहीं हैं, खाने के लिये रोटी नहीं है। मैं कैसे इस गवर्नमेंट के लिए कहूं कि उसने मुल्क की तरकी की है जब आजाद हो जाने

के बीस साल बाद भी हिन्दुस्तान के गरीब लोगों को, पिछड़े हुए लोगों को, बीकर सेक्शन को, वह रोटी कपड़ा और मकान भी मुहैया नहीं कर सकी है। इस के लिये बहुत जरूरी है कि प्लैनिंग जब होती है, फाइव इयर प्लैन जो बनती हैं उन में इन लोगों के लिये ज्यादा-रूपया रक्खा जाये। यह मुतालबा बहुत जायज है। और मैं समझता हूं कि जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा तब तक इस देश में जो समाजवाद का नारा दिया जाता है वह गलत साबित होगा और इस के रहते हुए अगर यह सोचा जाये कि 200 वर्षों में भी समाजवाद आ सकेगा तो वह नहीं हो सकता।

इस के अलावा जहां तक सर्विसेज का सवाल है, यह कहा गया था कि उन को नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जायेगा, लेकिन जितने लोग भी यहां बोले हैं, चाहे वह अपोजीशन के हो या गवर्नमेंट बेचेज के, सब ने साबित कर दिया है कि अभी तक उन लोगों को नौकरियों में पूरा परसेन्टेज नहीं मिला है, और हम को इस बात का बड़ा दुःख महसूस होता है। आज उन को परसेन्टेज है 1.59 क्लास 1 में और 2.51 क्लास 2 में। उन लोगों को जो 12½ परसेन्ट रिजर्व सीटें दी गई थी नौकरियों में, उन की हालत आज तक यह है। गवर्नमेंट हमारे ऊपर एहसान बहुत करती है कि यह किया है वह किया है, लेकिन 15-20 करोड़ आदमियों का हाल यह है कि अभी तक उन्हे कहीं जमीन नहीं मिली। जमीन आप के पास बहुत काफी बेकार पड़ी है मगर उन को दी नहीं जा रही है। हमारी गवर्नमेंट यह कह सकती है कि आज तो नौ स्टैंडस में नान कांग्रेस गवर्नमेंट हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट तो पिछले दो चार महीनों में ही

### [श्री साधूराम]

बदली हैं। पिछली दफे शेडयूल्ड कास्टस कमिशनर की रिपोर्ट पर बोलते हुए मैंने यह अलफाज कहे थे कि उन्हें जमीन दी जाये। एक तरफ तो हमारे यहां अकाल पड़ रहा है और हम अमरीका से जा कर भीख मांगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे काश्त करने वाले लोग हैं, उन को जमीन नहीं मिलती। जमीन बेकार पड़ी है लेकिन उन को नहीं दी जा रही है। जो लैंडलैस लोग है उन को जमीन नहीं मिलती है।

मैं एक और भी दुःख महसूस करता हूं कि हमारी पालियामेंट का बजट सेशन तीन या सवातीन महीने होता है, लेकिन शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्ज के मसले को हल करने के लिये दो तीन साल बाद जो शेडयूल्ड कास्टस कमिशनर की रिपोर्ट है उस पर विचार करने के लिये हम एक या दो दिन नहीं निकाल सकते। एक यह भी डिस्ट्रिक्मिनेशन देश में चल रहा है। मैं समझता हूं कि यह नहीं होना चाहिये और इस के लिये ज्यादा से ज्यादा टाइम दिया जाना चाहिये। जिन लोगों में से सयासत के चलाय वाले निकल कर आये हैं, उन की पूरी बात सुनने के लिये अगर गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं है तो यह बड़े दुःख की बात है।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि जमीन का जो मसला है वह हल नहीं हुआ, सर्विसेज का मसला हल नहीं हुआ। उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा रियायतें दी जाये तभी जा कर समाजवाद का नारा पूरा होगा, नहीं तो समाजवाद को लाने की बात तो क्या, कोई भी सुधार नहीं हो सकता। चूंकि बहुत ज्यादा कहने का वक्त नहीं है इस लिये मैं थोड़े में अपने सुझाव सामने रखना चाहता हूं। चूंकि मैं गवर्नमेंट

बेंचज की तरफ बैठा हुआ हूं इस लिये मैं मश्वरे के तौर पर अर्ज करना चाहता हूं कि एक पालियामेंट्री कमेटी मुकर्रर कर दी जाये शेडयूल्ड कास्टस और शेडलड ट्राइब्ज के लिये, जो गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट पेश करे। आज जो भी हालत इन पिछड़े हुए लोगों की है उस को दुरुस्त करने के लिये एक पालियामेंट्री कमेटी जरूर कायम होनी चाहिये।

इन लोगों को जो स्कालरशिपस दिये जाते है वह समय पर दिये जायें। फिर यह इतना विशाल मसला इस देश के लिये है कि इस के लिये एक सेपरेट मिनिस्ट्री अगर नहीं बनाई जायेगी तो मैं विश्वास नहीं करता कि इन लोगों के मसले कभी हल हो सकेंगे। मैंने पहले भी अपने प्लैनिंग और सोशल वेलफेयर मिनिस्टर श्री अशोक मेहता से कहा था कि वह बहुत बिजी आदमी हैं, वह काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उन के पास बहुत ज्यादा काम है, इस लिये मैं पुरजोर मांग करता हूं कि इस काम के लिये एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई जाये।

इस के बाद मैं यू० पी० एस० सी० के बारे में बतलाता हूं कि वहां पर शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्ज के रिजर्वेशन को पूरा करने के लिये कोई मेम्बर नहीं है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशनर्स में भी कोई मेम्बर नहीं है। सवाइनेट सेलेक्शन बोर्ड में कोई मेम्बर नहीं है। जब यह हालत है तो उन लोगों का रिजर्वेशन कैसे पूरा होगा?

प्लैनिंग कमिशन प्लैनिंग में जो रुपया उन लोगों के लिये मखसूस करे वह उन की आबादी के लिहाज से दिया जाना चाहिये और उन की आर्थिक तरक्की के लिये स्माल स्केल इंडस्ट्रीज कायम की जायें।

उनको ग्रान्ट दी जाय, उनकी कोम्पारेटीज सोसायटीज बनाई जाये। अगर यह सारे काम उन लोगों के लिये नहीं किये जायेंगे तो आने वाला समाज यह इजाजत नहीं देगा कि यह 15-20 करोड़ आदमी बैठे रहे, हम उन की तरफ चुपचाप देखते रहे और समाजवाद का नारा लगाते रहें। इस तरह से न जाने कब आपका समाजवाद का नारा पूरा होगा और कब उन लोगों की तरक्की होगी।

पार्लियामेंट के अन्दर प्रतिनिधित्व के लिये और मिनिस्ट्री के अन्दर प्रतिनिधित्व की अगर मैं मांग करूं तो उस का यह मतलब न समझा जाये कि मैं मिनिस्टर बनना चाहता हूं। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि उन को उन को आबादी के लिहाज से हर तरह की सहायता होनी चाहिये और हर जगह प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये।

**Mr. Speaker:** The hon. Member will sit down now.

We are adjourning for lunch now. After lunch the Minister will reply.

13 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after lunch at four minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

MOTION RE. FOURTEENTH AND FIFTEENTH REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES FOR 1964-65 AND 1965-66—contd.

**The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh):** Sir, I would humbly

suggest that members might be allowed to speak till 3 P.M. and after that the Planning Minister might reply.

**Mr. Deputy-Speaker:** There is a suggestion that the debate should continue till 3 O'clock and I request the hon. Minister to reply at 3 P.M. No further extensions should be asked for.

**Shri S. Kandappan (Mettur):** The extended time must be shared by the Opposition also.

**Mr. Deputy-Speaker:** We shall try to accommodate.

**Shri C. M. Kedaria (Mandvi):** Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me time. At the outset I am happy that the department is in charge of Mr. Asoka Mehta who is wedded to the cause of social welfare and he is trying to do his level best to the backward classes. It cannot be denied that the Five Year Plans have helped the development of tribals, but due to lack of integration of schemes and effective implementation, the impact on the tribal economy has not been commensurate with the expenditure incurred. After introduction of the panchayati raj, all development schemes including tribal programmes are implemented through the panchayati raj bodies in the districts. This has also created administrative problems about relations of officials and non-officials, location of schemes, allotment of funds, responsibility for implementation, etc.

Article 46 of the Constitution says:

"The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and in particular, of the scheduled castes and the scheduled tribes and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation."

In accordance with this policy, the Central Government have tried its level best. They have invented all-sided development programmes in the

[Shri C. M. Kedaria]

form of multipurpose tribal development blocks. The Central Government first thought of having 480 tribal development blocks. But at the end of the third five year plan only 417 were actually implemented. Under T. D. Block there is an area of 150 to 200 square miles earmarked for a population of 25,000. That means, 66 per cent are covered by these tribal blocks. But what about other sections. The population not covered by the tribal blocks is still in an under-developed condition. So, in the fourth plan, the Central Government have thought of an Area Approach Scheme which contemplates both concentration of effort in the tribal development blocks and a more integrated perspective in terms of a larger operational area. But there also whatever funds are to be spent on the tribal development blocks will not actually be spent towards the amelioration of the tribals. In the third five year plan, in all Rs. 1761 lakhs were allotted for the tribal blocks. But in the first four years of the third plan only Rs. 743 lakhs were spent and at the end of the fifth year of the plan Rs. 1017 lakhs were spent. This shows how the scheme is not working according to the scheduled programme. The schemes are implemented in a haphazard way and the benefits do not go to the class for whom the schemes are implemented. I would like that a well-thought-out programme should be worked out. I am happy, our Minister has now invented a new set-up in the administration with a post of Director-General who is to implement all the schemes. According to the Constitution, the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is to investigate and report to the President. I hope that this will work very well, but it is my impression that if there is non-official agency to look after the schemes of scheduled castes and scheduled tribes, the official agencies alone will not work, because we find at the end of 17 years that the schemes are not implemented

properly. I request the Government that on the basis of the Estimates Committee, the PAC and the Public Undertaking Committee, a parliamentary committee consisting of members of Parliament may be set up to look after all the schemes which are implemented by the Centre, by the State or by local bodies. It will then suggest, advise and guide the Government. It is my earnest request that this may be implemented.

Under article 344 of the Constitution special rights are given to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. At the end of 1970, these rights may be extended. There is a special provision under article 275 of the Constitution which has a very wide scope for special and further funds to be supplied for the amelioration and welfare of the Backward Classes. Till now the Parliament has not done anything in this respect. I request the Department of Social Welfare to approach the Central Government for further funds because when we approach the State Governments they say that the schemes which are not included in the Five Year Plans and which are not within the Five Year Plans; they are not able to implement those schemes whatever they may be. For example when we approach them under agro-industrial policy, loans to be granted towards the share capital, the State Governments are handicapped. Similarly, when we approach them for the processing society for the amelioration of the Backward Classes, there also they are handicapped. Therefore, the Central Government may be approached, under article 275 of the Constitution, for further more funds, so that their problems may be solved and within the Scheduled time limit, progress may be achieved.

Sir, the tribal economy is generally based on agriculture and forest. Generally, the tribals live in forest and hill areas and, as far as the agricultural economy is concerned, it

concerns more with shifting cultivation. In the forest, under the old forest policy formulated in 1894, there were some special privileges and rights for the tribals. Later on that was formulated in 1934 wherein privileges were treated as concessions for the tribals. Under the new policy the rights were withdrawn and only the concessions remained. According to the policy relating to concessions to tribals, they are to get permits, licences and permissions. The result is this that the tribals are very much harassed by the forest officers. Therefore, whatever concessions and rights were there for the tribals, should be restored. The concessions and rights relating to free timber for housing, cultivation etc. should also be given to them. The rights for lifting of leaves, free timber for their houses etc., that were withdrawn should be given back to them.

There is one more point that I would like to bring to the notice of the House. By the implementation of the big national projects, because most of the projects are located in the tribal areas, most of the tribal people in these areas are displaced. There is no provision in these projects for rehabilitating these persons who are displaced. About 14,113 families were displaced and 62,238 acres of land are taken away. Out of this only 3477 families have been rehabilitated and 8314 acres of land are granted. I suggest that the Central Government should take special care for the rehabilitation of these people and rehabilitation schemes should be included in the project itself and adequate financial provision must be made for them.

Lastly, I congratulate the Minister of Social Welfare who is enthusiastically carrying out all the schemes. In future, we hope, there will be no complaints.

**Mr. Deputy-Speaker:** Before I call the next hon. Member I would make one request. As the hon. Minister is taking note of every suggestion that is made on the floor of the House, as 1884 (D) L.S.D.—8.

far as possible repetition of the same suggestion should be avoided so as to save time. Secondly, everybody should restrict his remarks to five minutes as far as possible. I have to accommodate some Members from this side also. Shri Barupal.

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** उपाध्यक्ष महोदय, लगातार पांच व्यक्ति बांग्रेम से बोल चुके। कन एन्ड भी कांग्रेस सदस्य ने किया था और आज प्रारम्भ भी वहीं किए हैं। हमको भी मौका मिलना चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय :** हम कोशिश करेंगे।

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** आप कोशिश करोगे लेकिन दोगे नहीं।

**श्री प० ला० बारपाल (गंगानगर) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका और संसदीय कार्य मंत्रा का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आदिवासियों और हरिजनों की भावनाओं की कदर करते हुए एक घंटे का समय बढ़ाया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं अपनी सरकार से यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि जितने लोगों ने चाहे वह आदिवासी हों चाहे हरिजन हों चाहे दूसरे लोग हों, उन्होंने आदिवासियों और हरिजनों के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये हैं सरकार को, उनके ऊपर सरतार अमल करे तो अच्छी बात है। 1964-65 का रिपोर्ट पर आज 1967 में विचार किया जा रहा है, इसी से आप समझ सकते हैं कि इनकी कितनी उपेक्षा की जाती है। बहुत से लोगों ने कहा कि बहुत से हरिजन और आदिवासी ईसाई बन जाते हैं। मैं इस सम्बन्ध में हिन्दुओं की उपेक्षा वृत्ति के ऊपर एक संकेत करना चाहता हूँ कि :

हिन्दुओं में अगर बेइबाई न होती।  
तो भारत में ईसाई तभी न होती॥  
अगर प्यार दिन से अछूतों को करते।  
तो यह काम प्यारों ईसाई नहंती॥  
कटा करके चाँदी न बनते विश्वी।  
अगर इनमें यों दबदबाई न होती॥



[श्री ५० ला० बालूपाल]

अगर पाठ गीता का इन को पढ़ाते ।  
तो कुरां बाइबिल की पढ़ाई न होती ॥  
मन्दिरों में इन्हें गर रुकावट न होती ।  
तो मसजिद में सुरती लगाई न होती ॥  
अहिंसा धर्म का जो उपदेश देते ।  
आज गउओं की गरदन कटाई न होती ॥

यह न ईसाई बनते न मुसलमान बनते ।  
और आज इन्हीं का मनोवृत्ति के कारण  
हिन्दुस्तान के दो टुकड़े हुए, नहीं कोई और  
कारण नहीं था । हम न अछूतस्तान चाहते  
हैं न सिखिस्तान चाहते हैं । हम चाहते हैं  
कि एक हिन्दुस्तान हो । लेकिन आजादी  
हुए आज बीस साल हो गए और बीस साल के  
बाद भी यह कहना पड़ रहा है कि आप केवल  
अगर यह रिजर्वेशन न रखते तो हमारे जैसे  
गरीब आदमी पार्लियामेंट में न होते । लेकिन  
यह स्थिति यहां है कि हमारे जैसे 50-80 या  
सौ संसद सदस्य आ जाते हैं, कुछ विधान  
सभाओं में आ जाते हैं लेकिन बाकी हरिजनों  
और आदिवासियों की स्थिति ज्यों की त्यों  
बनी हुई है । मेरा आपसे निवेदन है,  
विशेष कर के योजना मंत्री से  
मैं कहना चाहता हूं कि इस योजना को आप  
को समाजवादी तरीके से लेना पड़ेगा ।  
अभी तक आपकी योजना पूंजीवादी तरीके  
की है । अगर आपको क्रांतिकारी कदम  
उठाने हैं तो आपको एक आर्थिक क्रांति  
करनी पड़ेगी, आपको एक सामाजिक क्रांति  
करनी पड़ेगी, आपको धार्मिक क्रांति करनी  
पड़ेगी और जब तक इन के अन्दर परिवर्तन  
नहीं करेंगे इस देश का उत्थान नहीं हो सकता ।

कुछ भाइयों ने कहा कि अन्तर्जातीय  
विवाह होना चाहिए । मैं इस बात में विश्वास  
करता हूं कि मनुष्य मात्र सब एक है । लेकिन  
जहां पर एकतरफा छूट होगी अन्तर्जातीय विवाह  
की तो मनुष्य की नेचर होती है भड़कीली  
चीखों की तरफ, आडम्बर की तरफ पूंजी की  
तरफ जाने की और हमारे बच्चे और औरत तो  
गरीब हैं, वह सारे के सारे ऊंचे लोग उनको  
उठा कर ले जायेंगे और हम गरीबों के पास

कोई भी हरिजन लड़की नहीं आयेगी ।  
अगर हमारी स्थिति सुदृढ़ है और मैं आपसे  
कहना चाहता हूं, मैं आज संसद का सदस्य हूं,  
मेरे लड़का नहीं है, मेरे पास जमीन भी है,  
मैं कुछ छिपाना नहीं चाहता, पार्लियामेंट का  
सदस्य बनने के बाद कितने ही उच्च जाति  
के लोगों ने मुझे आफर किया कि हम अपनी  
लड़की देना चाहते हैं । लेकिन मैंने कहा कि  
अगर करूंगा तो मैं अपनी जाति में करूंगा  
क्योंकि कोई गरीब आयेगा तो कम से कम  
रोटी तो खायेगा ।

मैं आपसे कहना चाहता हूं, हरिजनों  
की नोकरियों में क्या हालत है, यह आपके  
सामने है । लेकिन क्या कुचक्र चलाया  
जाता है कि हरिजन लड़का जब मैट्रिक में  
आता है तो उसको कम से कम तीन साल तक  
फेल कर दिया जाता है जानबूझ कर  
रिमाक गन्दा दे दिया जाता है, क्योंकि वह  
चाहते हैं कि पांच वर्ष की जो रिजर्वेशन इनको  
मिली हुई है, वह पूरी न होने पावे । । क्योंकि  
अगर वे लोग पढ़ लेंगे, तो आगे बढ़ेंगे, तरबकी  
करेंगे, इसलिये हर तरह की रुकावटें इसमें  
डालते हैं । इस हिन्दु समाज की कौन कौन  
सी खुराफात आपको बताऊं । हम तो सिर्फ  
यह चाहते हैं कि हमको जमीन दो, विजनेस दो,  
हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार करो—  
इस के अलावा हम कुछ नहीं चाहते हैं ।  
हम रिजर्वेशन भी नहीं चाहते हैं, रिजर्वेशन  
मांगना नालायक आदमियों का काम है,  
लेकिन आज आगे बढ़ने के लिये हमको जो  
मोका नहीं दिया जाता है, वह मोका हम को  
मिलना चाहिये ।

राजपूती किसी के बाप की नहीं है ।  
हम भी उनसे अच्छे काम करके दिखा सकते  
हैं । मैं खुद एक मिलिट्री मैन हूं, रिटायर्ड हूं  
और एक चमार का लड़का हूं—बड़े बड़े  
ठाकुरों का मैंने मुकाबला किया है कम्पीटीशन  
में, इसी पार्लियामेंट के दो तीन राजाओं  
के मुकाबले में मैंने स्वर्णिय पंत जी के नाम का

बढ़ल लिया। आप हमको मौका नहीं देते हैं अगर हमको मौका मिले तो कम्पीटीशन से भी हम आगे आ सकते हैं।

आज जो छात्रवृत्ति सरकार की तरफ से दी जाती है, वह हमको नहीं मिल पाती है। दूसरे लोग छात्रवृत्ति को बढ़ाने के लिये कहते हैं, लेकिन मैं यह कहता हूँ कि जितनी छात्रवृत्ति इस समय रखी गई है अगर वही ईमानदारी से हमें मिल जाये तो ठीक है। यह बड़े धर्म की बात है, दूर मरने की बात है, आप इसको ठोक नहीं करेंगे तो कौन करेगा।

आप जो आदेश निकालते हैं, प्रान्तीय सरकारें उनको अपने यहां लागू नहीं करती हैं। हम कब तक इस तरह से चलने रहें, कब तक भोख मांगते रहें। आप इस बात को समझ लीजिये कि अब जमाना बदल रहा है, क्रांतिकारी जमाना चल रहा है, उधर वाले हों या उधर वाले हों, मैं सब को कहता हूँ कि आदिवासी और हरिजन हिन्दुस्तान की समाज के प्राण हैं। इन्होंने अपना सब कुछ समाज को दिया है, लेकिन इस समाज ने इन को क्या दिया—दरिद्रता, अछूतपन, अहेलना। कभी हमारा नाम आदिवासी रख देते हैं, कभी हरिजन कर देते हैं, जिसकी जो-मर्जी आती है, वही नाम धर देते हैं।

15 वर्ष से इस पार्लियामेंट का मेम्बर हूँ—बाबू जगजीवन राम कहते हैं कि चमारों की चढ़ आई है—मैं उनको क्या कहूँ, मेरी समझ में नहीं आता कि क्या चढ़ आई है। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जिधर हरिजन और आदिवासी रहेंगे उधर ही पलड़ा भारी रहेगा, जिनके साथ ये रहेंगे उन्हीं की जयजयकार होगी बाहे वह कांग्रेस हो या दूसरे लोग हों। इनकी उपेक्षा होगी तो न कांग्रेस की सरकार रहेगी और न दूसरों की सरकार रहेगी।

श्री आराम दास (मुरैना) : उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं हमारे जो नेतागण हो चुके हैं उनकी विचारधारा आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ। उनका कथन है

कि कोई मनुष्य या तो निरोग रहेगा या रोगी। यह नहीं हो सकता कि वह तिहाई निरोग हो और दो तिहाई रोगी। इसी तरह से यह राष्ट्र भी या तो सारे का सारा स्वतन्त्र रहेगा या सारे का सारा परतन्त्र। यह नहीं हो सकता कि देश में कुछ लोग स्वतन्त्र रहें और शेष परतन्त्र। देश की अनुसूचित जातियाँ और आदिम जातियाँ यदि गुलाम और परतन्त्र रहेंगी तो बड़े कहे जाने वाले लोग भी स्वामी और स्वाधीन न रह सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, छूतपन के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूँ कि संविधान की 11वीं धारा के द्वारा छूतपन का अन्त कर दिया गया है, इसको वहन करने वालों को दण्डनीय अपराधी माना जायेगा। परन्तु श्रीमन्, मुझे बड़े दुःख और आश्चर्य के साथ कहना पड़ता है कि स्वतन्त्रता की प्राप्ति के 20 वर्ष बाद भी छुप्राछुप का अन्त नहीं हुआ, भारत सरकार इस कलंक को मिटा नहीं पाई है। अस्पृश्यता का कम होना तो दूर रहा, यह अनेकों रूप में हमारे देश में बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को पग पग पर अपमान ही नहीं, अनेकों कष्ट और अत्याचार भी भोगने पड़ने हैं।

कहा जाता है कि बड़े बड़े शहरों में अस्पृश्यता का अन्त हो गया है, लेकिन यह बात सत्य से परे है। आज भी दफ्तरों में, सरकारी बस्तियों में तथा सार्वजनिक व्यवहारों में इसका नंगा नाच देखने को मिल जाता है। इन जातियों के पढ़े-लिखे व्यक्तियों के साथ अस्पृश्यता के कारण ही व्यांगत्मक तथा अग्रमानजनक व्यवहार किये जाते हैं। इस वर्ग के सभी सरकारी कर्मचारियों को वार्षिक रिपोर्ट पढ़ कर शराब की जाती है, उनकी अति में रुकावट डाली जाती है तथा इस जाति के अफसरों तथा कर्मचारियों को अनेकों झूठे मामलों में फँसाने का प्रयत्न करके इन्हें नौकरियों से हटाया

## [श्री आत्म दास]

जाता है तथा इन पर झूठे मुकदमे चलाये जाते हैं तथा इनकी ग्रामों में तो बेहद दयनीय दशा है, इनको अनेक प्रकार से सताया जाता है और इनके साथ घोर अत्याचार किया जाता है। चरागाहों, सार्वजनिक कुओं, तालाबों से आज भी पानी नहीं लाने दिया जाता तथा पहले की तरह की रुकावटें डाली जाती हैं। ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण हैं जहां इन लोगों को सवर्ण हिन्दुओं की ओर से अनेकों प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। यह तथ्य अनुसूचित जातियों की जो रिपोर्ट आई है उसके भी नीतिमात्र प्रकट है। सरकारी नौकरियों में समान अवसर और सरकारी पदों पर नियुक्ति के अधिकार से दलित जातियों तथा आदिवासी जातियों को सदियों से वंचित रखा गया है और वही दशा वर्तमान में भी है। स्व० माननीय पंडित नेहरू जी तथा अन्य नेताओं ने यह मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया है कि दलित जातियों की आर्थिक तथा शिक्षा सम्बन्धी पिछड़ी अवस्था है, अतः उन्हें हर प्रकार से सम्बन्धित संरक्षण की आवश्यकता है। नौकरियों में समान अवसर की नीति से इन जातियों की वर्तमान दशा में कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये प्रतियोगिता में दूसरों से मुकाबला नहीं कर सकते। जो मुकाबला भी करते हैं उन्हें अधिकारीगण अपनी पुरानी मनोवृत्ति के कारण अयोग्य ठहरा देते हैं। इसलिए जब तक इनके लिए पदों पर नियुक्ति के लिए स्थान सुरक्षित न हों और उन सुरक्षित स्थानों पर इनके सर्वश्रेष्ठ उन्मीदवारों को नियुक्ति की कोई सन्तोषप्रद व्यवस्था न हो तब तक इस घारा से उन्हें कोई सहायता नहीं मिल सकती। इनकी अवस्था को सुधारने के लिये सब से पहले शिक्षा की आवश्यकता है, उसके बाद इनमें नवीन तथा सम्माननीय उद्योगों व व्यवसायों के विकास की आवश्यकता है। जब ये लोग लाभ-प्रद उद्योग धंधे और उच्च व्यवसाय करने लगेंगे और सरकारी उच्च

पदों पर कार्य करने लगेंगे, तभी इनका सुधार होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अस्पृश्यता निवारण के हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त महोदय की रिपोर्ट द्वारा जो सिफारिश की गई है, उस पर तुरन्त असरकारक अमल किया जाय। मेरे क्षेत्र में अधिक से अधिक संख्या में आदिवासी तथा हरिजनों की आबादी है, मैं मीरता क्षेत्र से आया हूँ, वहां पर दस्युओं का इतना जोर है कि उसमें हरिजन आदिवासियों हो नहीं, बल्कि सवर्ण जातियां भी अनेक प्रकार से भयभीत हैं। उस क्षेत्र में उद्योग धंधे स्थापित करने की विशेष रूप से आवश्यकता है, क्योंकि वहां की हरिजन जातियां हो नहीं, बल्कि सभी लोग बड़े गरीब हैं तथा बेकारी के कारण ही उनको डकैती आदि के कार्य करने पड़ते हैं। यदि वहां पर कोई ऐसा उद्योग धंधा खोल दिया जाय, जिससे वहां के हरिजन, आदिवासी ही नहीं, बल्कि सवर्ण गरीब लोगों को भी काम मिल सके तो उससे डकैती समस्या के हल करने में बड़ी सहायता मिल सकती है।

जाति-भेद को शीघ्र से शीघ्र मिटाया जाय। सरकार जाति-भेद को किसी भी रूप में स्वीकार न करे अर्थात् जाति के कारण न तो किसी को कोई रियायत दी जाय और न किसी पर कोई रुकावट लगाई जाय। सब के लिये उन्नति के अवसर हों। सरकारी नौकरियों, भूमि खरीदना, सेना और पुलिस, सरकारी नौकरियों में भरती होना किसी जाति विशेष के मनुष्यों का इजारा न हो।

जिस प्रकार जनगणना में सवर्ण हिन्दुओं का "जाति" का खाना निकाल दिया गया है, उसी प्रकार सरकारी कागजातों में से इन के हरिजन, आदिवासी विभिन्न नामों का खाना निकाल दिया जाय। अस्पृश्यता निवारण का दृढ़ता से पालन किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जो सरकारी नौकर हैं, अधिकारी लोग हैं उनको पदोन्नति तो दूर रही ऐसा खयाल किया जाता है जैसे मैंने पहले कहा कि उनका रिकार्ड खराब कर दिया जाता है। इसी को मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। एक व्यक्ति अनोहर लाल यादव भिड़ जिले में गौहद तहसील में नापतौल विभाग में इंस्पेक्टर था। उसके कामों से खुश होकर अखबारों में उसको बड़ी प्रशंसा की जाती रही लेकिन जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वह हरिजन है, अछूत जाति का है तो पहले उसका वहाँ से रायपुर ट्रांसफर कर दिया लेकिन वहाँ जाकर भी उसने कंट्रोलर इनचार्ज का अच्छा काम अंजाम दिया और 11 महीने तक वह अच्छी तरह वहाँ पर काम करता रहा। अब अच्छे काम के लिए उचित तो यह था कि उसकी पदोन्नति की जाती, लेकिन जब उसकी तरक्की होने का अवसर आया तो उसे बजाय तरक्की देने के बिलासपुर जिले में जांजगीर तहसील में पहुँचा दिया गया और आज वह वहाँ पर 7 वर्ष से पड़ा हुआ है। न तो उसकी कोई पदोन्नति की जाती है और न उस का ट्रांसफर किया जाता है।

**Mr. Deputy-Speaker:** Mr. Katham. We have hardly half an hour left, but there are ten more names. So, I would request the hon. Member to finish in five minutes.

**Shri B. N. Katham (Jalpaiguri):** I thank you very much for giving me the opportunity to take part in this debate. I would not have taken the time of the House if I had had no responsibility for my constituency where there are a large number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

I have heard the hon. members who spoke on this debate for the last two days, and, by and large, I agree with those hon. members who advocated for betterment of the conditions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

The problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are the same everywhere in the country. They have not got sufficient scope for their economic development. Almost all of them live in rural areas and forests. Therefore, unless the entire agricultural community is uplifted, the poor lot of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is not going to be improved. Everybody will admit that they do not get facilities from Government in respect of agricultural loan for their agriculture. Many of them are so poor that they cannot provide sufficient security or mortgage required for getting loans. The result is that 90 per cent of them do not get loans from Government. All credit facilities for other schemes like small scale industries, fisheries, etc., could not be availed of by them for want of securities.

In respect of their educational facilities, I may point out that the programme of compulsory primary education as provided by the Constitution has not spread to the interior tribal villages. Their literacy has not increased to any appreciable degree..

I am glad that the Government have ultimately come to realise that functioning of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is not sufficient for the measures to be taken for the development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Therefore, they are proposing to have a Director-General appointed to initiate and implement the developmental programmes in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I very much welcome all these steps taken by our Government.

At present, all the developmental programmes are formulated by the State Governments at their sweet will. Even the Centrally sponsored schemes which are fully financed by the Central Government are also prepared and sanctioned by the State Governments. From this position one can easily understand that the Centre has no hand in development matters

[Shri B. N. Katham]

although this Government is directly responsible to Parliament. I am sure that this anomaly will now go and the Director-General will be responsible to the Central Government for the developmental programmes regarding Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Although fifteen years have passed since the appointment of the Commissioner, no substantial development has been achieved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Their economic position remains the same as it was previously. Even their elementary needs like drinking water supply, primary education, public health, village roads, etc., have not been sufficiently provided.

Now I come to my State, namely, West Bengal. In West Bengal the population of Scheduled Tribes is more than 20 lakhs, but substantial amounts have not been spent for their development. Sufficient numbers of tribal development blocks have not been started. Large pockets inhabited by tribals like Meches, Ravas, Garos, Uraos, Mundas, Saotals are yet to be covered by such blocks.

Therefore, I request the hon. Minister to see that the newly appointed Director takes the necessary steps to provide such development blocks in the areas where there are tribal people who have not so far benefited by the facilities to the Scheduled Tribes in general.

Here, I want to draw the attention of Government to a particular scheme. It relates to a proposal submitted by a large section of the tribal and Scheduled Caste people numbering over 50,000 persons, to construct a road through the tribal villages, connecting National Highway No. 31 in Jalpaiguri and Cooch-Behar districts. This road will serve as a vital link road from the interior tribal areas to the National Highway.

I may draw your attention to the fact that the tribal areas of my con-

stituency are very backward in communication. Therefore, I very strongly urge the Central Government to take up this programme as a Centrally-sponsored scheme for which I think only a sum of Rs. 20 lakhs will be required. The people have already urged the State Government in this regard but there is no proper response from the State Government.

There is urgent need for a tribal development block in the district of Jalpaiguri for the economic development of the tribal people there.

There is a large concentration of tribal people in Kumargram Thana area. Kamakshaguri is a centrally located place in the tribal areas of the eastern part of Jalpaiguri district. I do not know why Government have not so far started a tribal development block in this area.

The development of North Bengal will not be complete with this block alone. Therefore, I suggest that another block should be provided in the Cooch-Behar district. There is a concentration of tribal people in Tufanganj area in Cooch-Behar district where another blocks should be started as early as possible.

I know that I am going into details but I cannot help saying that development measures should be taken along these lines, keeping in view the particular needs of the tribal people.

I fervently hope that the Director-General will keep these suggestions in mind.

**Mr. Deputy-Speaker:** Now, Shri Siddayya. The hon. Member should confine his remarks to five minutes.

**Shri Siddayya (Chamarajanagar):** I cannot finish in five minutes. If I have to finish in five minutes then I would rather keep quite.

**Mr. Deputy-Speaker:** Let him take his time. Then, what can I do?

**Shri Siddayya:** In five minutes it is not possible for me to do justice to the subject.

Last year, when the report for 1963-64 was discussed in this House, the Deputy Minister of Social Welfare who had initiated the debate had promised that she would reply to the debate in the end. That promise has not been fulfilled so far. There was no difficulty in her getting at least ten or fifteen minutes and then giving a reply. This merely shows the amount of interest that Government are evincing, with regard to matters connected with Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

This year, we find that the reports for 1964-65 and 1965-66 are being discussed. There was a convention in this House that before the report for a particular year was discussed, a report on the action taken on the report of the previous year used to be laid on the Table of the House invariably. Last year, when the report for 1963-64 was discussed in the House, on that very day, namely the 18th August, 1966, the Deputy Minister had placed on the Table of the House a statement showing action taken on the report for the previous year. But this time that convention has been given the go-by.

**An hon. Member:** No action has been taken.

**Shri Siddayya:** Without that statement showing the action taken on the report for the previous year, we cannot fruitfully discuss these reports. This shows that the interest taken by Government is decreasing gradually.

**An hon. Member:** Topple it down.

**Shri Siddayya:** I may also point out that in the Second Lok Sabha, a copy of the statement showing action taken on the previous reports was not merely placed on the Table of the House but was also supplied to each Member. In the Third Lok Sabha the statement was only laid on the Table of the House and some copies were kept in the Library of Parliament, but copies were not supplied to the Mem-

bers. In the Fourth Lok Sabha, neither the statement is supplied to Members nor is it placed on the Table of the House. That shows the progress that we have made during all these years. I think no purpose can be served by discussion without a statement showing the action taken on previous recommendations. I have tabled an amendment to the motion moved by the hon. Minister suggest in the appointment of a committee of Parliament to keep a watch on the implementation of the various recommendations made by the commissioner from time to time.

I have gone through all the Reports of the Commissioner and I find that from the very inception of his office, he has been complaining that States are not sending reports in time and even where they do the reports are incomplete. This is the handicap under which he has been working all these years and I do not think the Government has in any way helped him to discharge handicaps. I felt that in spite of these handicaps, I felt that all the three Commissioners who had held this office so far, have done their job well. They have maintained their independent status and have given very valuable reports.

Coming to the implementation of the recommendations if you go through the statement of action taken on reports, you will find that some States have not replied at all, some have given vague replies some have just said 'noted', 'under consideration', 'may be considered', 'kept in view', 'agreed in principle' etc. This is the way these recommendations have been treated by State Governments. So you find that among the State Governments some are good, some bad and some very indifferent also.

I will give one or two instances. I take my own State, Mysore. Out of 231 recommendations in the Report for 1962-63, only 8 have been replied to, not a question of having implemented them even. About the others, I do not know what has happened. I do

[Shri Siddayya]

not know whether the Commissioner has written to them, whether the Government of India have followed it up to get the replies from them.

If you scrutinise the recommendations—I will go back to the action taken on the Report for 1961-62—these are very simple recommendations which any State Government could easily have implemented, but which they have not done. For example, recommendation No. 12 says that inscriptions should be engraved on all public wells warning people against prevention of use of these wells by Harijans, and that if anyone did so, he will be punished under the Untouchability (Offences) Act. The Mysore Government have accepted the recommendation and also stated that boards may be put on the wall of public wells to this effect. My hon. friends from Mysore will corroborate me when I say that nothing has been done and this is still on paper only.

Another very simple recommendation, preliminary also, is No. 16—licences should be issued to haircutting saloons and restaurants on condition that they display in a prominent place a notice that there will be no discrimination against Harijans. The action taken by the Mysore Government is that panchayats and local boards have been asked to implement this. This was done in 1961-62. But so far nothing has been done.

I can go on quoting instance after instance in this vein, but the time at my disposal is short. Let me take up implementation by the Central Government. One of the recommendations in the 1962-63 Report is that the Social Welfare department should make arrangements to give training to scheduled castes and scheduled tribes for ministerial posts in the Central Secretariat Training School at Delhi. Four years have passed; still the Central Government have not done anything. On the other hand, they are asking State Governments to implement some of the other recommenda-

tions. Since the Central Government themselves do not implement the recommendation pertaining to them made by the Commissioner, what moral right have they to ask State Governments to implement them?

Another recommendation refers to the reservation to be made for scheduled castes and scheduled tribes in statutory organisations, semi-government institutions and public sector undertakings. The Central Government did not accept it as it is. They referred it to the Law Ministry. That Ministry took its own time to give its opinion. Now they have said that it can be made applicable. It is only after this that instructions have been given to all the departments. We find in the Report that of the many institutions covered by this, only 63 statutory bodies have agreed to implement it, not that they have actually implemented it. I find they are employed only in class three and class four; in class one they have not made any reservations, and the Central Government has not done anything so far in regard to that.

Coming to the High Courts and Supreme Court, I do not mean to say that Judges should be appointed without qualifications, but in the class one and class two posts, also class III and IV, is there any reservation? They are considered to be fountains of justice, and even in the fountains of justice, the scheduled castes and scheduled tribes have not been able to get justice. Only recently I think the Home Minister has requested the Supreme Court and High Courts to make reservations.

There was a seminar arranged by the Planning Commission in 1964 which made very valuable recommendations which have been incorporated by the Commissioner in his report. The recommendation refers to the appointment of a central executive authority to nominate candidates against reserved vacancies. The action taken as found in the report is

that the Director-General of Employment and Training himself nominates the candidates to the reserved seats, and therefore there is no need to have a duplicate authority. I put a question to the Labour Minister, Unstarred Question No. 3783 on 28th June, 1967, and the Labour Minister has categorically denied it. Yet, our friend Mr. Vidya Charan Shukla was again repeating yesterday that there is a central executive authority which is able to do it. He has misled the House by giving wrong information. That shows how the Government is functioning.

In 1958 there was a conference of Chief Ministers under the chairmanship of Pantji, who was the Home Minister then. A resolution was passed. It is a very simple resolution, that the name Harijan should be removed from the existing institutions, hostels or colonies wherever it exists, because it had reference to untouchability. Not only were the Chief Minister party to this resolution, but also the Government of India because the Home Minister was also present and it was under his chairmanship that it was done. But even today you find in so many schools, hostels etc., that the name Harijan is still there. Not only that. In the Central Government they have got a Central welfare Board for Harijans. Even today it is called as the Central Harijan Welfare Board.

**Mr. Deputy-Speaker:** May I request him to conclude?

**Shri Siddayya:** I will take only two minutes. If it is useful, I will speak. Otherwise, I will keep quiet.

In the last report, i.e. 1965-66 report, the Commissioner has made a recommendation, a very important one, that to enable this organisation, i.e. the Commissioner, to function effectively, action has to be taken to fill all the vacant posts and sanction some additional posts in the regional offices. Do you know the action taken

by the Government? Instead of helping the Commissioner by giving him the required posts, they have actually abolished all the 17 regional offices in the various States, and my own feeling is that thereby, instead of helping him, they want to curtail his ability to make his report. The Commissioner has got a unique position under the Indian Constitution. My own feeling is that he is the champion of the safeguards, provided for the scheduled castes and scheduled tribes in the Constitution. If he is not given the adequate staff that he requires, I think he will fail to do his duty properly, and therefore I request the Minister to reconsider the whole decision, and give him all the facilities which he requires including these 17 regional offices which he had till yesterday in all the States. The point now is how to get the recommendation implemented. The state governments are not implementing it, nor is the central government implementing. The constitution-makers were very wise in making a provision that this report should be placed on the Table of the House each year. The object of making such a provision is to make Parliament responsible for implementing it. Since the whole House cannot do it, it should appoint a parliamentary committee which the commissioner has also recommended. Therefore, my amendment for the appointment of a parliamentary committee is very important and I hope the government will accept that amendment and that the whole House would support the appointment of this committee.

**श्री मोलू प्रसाद (बांसगांव):** सब से पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरियों में अन्तर्जातीय विवाह करने वालों को प्राथमिकता दी जाए, इसको एक योग्यता माना जाए। जब तक यह काम नहीं होगा तब तक जातपात और भेद भाव खत्म नहीं होगा। वैसे तो सामाजिक और सांस्कृतिक क्रान्ति का होना आवश्यक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यह उपाय



[श्री मोहन प्रसाद]

का जो मामला है यह सामाजिक ही नहीं है बल्कि बहुत कुछ आर्थिक है। चार हजार मासिक पाने वाला आदमी जोकि चाहे ब्राह्मण ही हो वह एक हजार पाने वाले ब्राह्मण के यहां अपने लड़के या लड़की की शादी नहीं करना चाहता है, उसके यहां रिश्ता जोड़ना नहीं चाहता है। इसी तरह से एक हजार पाने वाला जो हरिजन है वह कम वेतन पाने वाले हरिजन के यहां अपना रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता है और जोड़ता भी नहीं है। मैं ब्राह्मणों और हरिजनों से भी कहना चाहता हूं कि अगर यही स्थिति रही तो देश रसातल को चला जाएगा।

आप यह भी देखें कि 1970 में रिजर्वेशन समाप्त हो रहा है। सभी कांग्रेसियों के रिश्तेदार नौकरियों में पड़े हुए हैं। 1970 के बाद उन को काम पकड़ कर नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। जितने वजीर हैं सब के रिश्तेदार नौकरियों में हैं और जब यह रिजर्वेशन समाप्त होगा तब उनके इन रिश्तेदारों को काम पकड़ कर निकाल दिया जाएगा।

हरिजनों के नाम पर जो संस्थाएं बनी हुई हैं वे हरिजनों की भलाई के कोई काम नहीं कर रही हैं। मैं उदाहरण देता हूं। हरिजन सेवक संघ है। दलित वर्ग संघ है। ईश्वर शरण आश्रम, इलाहाबाद है। भारतीय दलित सेवक संघ, पूना है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली है। हिन्दू स्वीपर्स सेवक समाज, नई दिल्ली है। ये जो सब संस्थाएं हैं ये कांग्रेस के लिए वोट बटोरू दफ्तर हैं। ये हरिजनों की भलाई के कुछ भी काम नहीं करती हैं और इन को बीस वर्ष में जितना धन मिला है, जितनी सहायता मिली है उसको ये खा पका कर बैठ गई हैं। हरिजनों की जो स्थिति है वह वैसी की वैसी है। इस तरह से जो रुपया दिया जा रहा है उसका कुछ भी लाभ हरिजनों को नहीं मिल रहा है और देश रसातल को जा रहा है।

हरिजनों के साथ क्या क्या अत्याचार होते हैं इसको आप देखें। 14 जलाई को श्रम सेवा पुनर्वास मंत्रालय, गोरखपुर ने अपने यहां के तीन लोगर डिबीजन क्लर्क्स, जिन के नाम हैं रामजी प्रसाद, परदेसी और राम करन नोटिस दे दिया है कि उनकी सेवायें 15 अगस्त, 1967 से समाप्त कर दी जाएंगी। सात आदमी वहां हैं जिन में से तीन को निकाला जा रहा है। इसको आप देखें। अगर इसी तरह से चलता रहा और यही रवैया आपका रहा तो 1970 तक जितने गैड्युल्ड कामेंट लोग दफ्तरों में हैं जब उनके लिए रिजर्वेशन समाप्त होगा तो उनको काम पकड़ कर बाहर कर दिया जाएगा। जैसा मैंने पहले कहा है कि हरिजनों को ऊपर उठाने का एक ही तरीका है कि अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाए और इसको एक योग्यता माना जाए सरकारी नौकरी के लिए।

एक सार्वजनिक विचार : अपनी गवर्नमेंट से शुरू कीजिये।

श्री मोहन प्रसाद : बन्धु अपने साधनों और अपनी बुद्धि और अपनी कर्मठता पर जीत कर नहीं आए हैं दूसरे के साधनों और बुद्धि और कर्मठता पर जीत कर आये हैं और दलाल पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं। अगर इन दलालों ने हरिजनों की समस्या को सुलझाने की कोशिश की होती, इस समस्या को हल करने की कोशिश की होती तो आज तक यह समस्या हल हो गई होती। हरिजनों को जो सुविधायें मिलती हैं वे हरिजनों के सवण खा गए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार सही नीति नहीं बनाती है, हरिजनों की समस्यायें हल नहीं हो सकती हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि अन्तर्जातीय विवाह करने वालों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए, जो व्यक्ति अन्तर्जातीय विवाह करें उनको पहले सरकारी नौकरी दी जाए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से रोजगार में अपने हरिजनों के लिए सीटें, रिजर्व की हैं उसी तरह से कोटा, परमिट

लाइसेंस आदि के मामले में भी इनके लिए कोटा रिजर्व कर दिया जाना चाहिए। आजकल हरिजन दो ही मुख्य काम करते हैं सूअर पालना और पाखाना साफ करना। पहले मुर्गी भी पाला करते थे लेकिन अब सबगों ने भी मुर्गी पालने का काम शुरू कर दिया है। सूअर पालना और पाखाना साफ करना सबगों ने नहीं शुरू किया है। वे भी दूसरे उद्योग धंधों में हिस्सा ले सकें। इसका लिए यह जरूरी है कि परमिट, लाइसेंस, कोटा आदि में उनको भी हिस्सा मिले (इंटरप्राइज) उधर तो बारात है और हम दो चार ही आदमी हैं इस तरफ। लेकिन जो सही बात है वह तो कहनी ही पड़ती है।

एक माननीय सदस्य : आप की सरकारें क्या कर रही हैं ? उनको कहिये न।

श्री मोलू प्रसाद : हमारी सरकारें जो कर रही हैं, धड़ल्ले से कर रही हैं। नौ प्रान्तों में आप की सरकारें गिर गई हैं। आठ में अभी हैं। वे भी गिर जायेंगी। वे भी चारों खाने चित गिर जायेंगी। 1972 आने दीजिये, आपकी सरकार यहां भी खत्म होने वाली है।

मैं मंत्री महोदय से अन्त में इतनी ही प्रार्थना करता हूं कि वह एक संसदीय समिति नियुक्त करें जो सारे काम हो रहे हैं देश में उनका निरीक्षण करे। वह समिति जो काम हो रहे हैं उन में सुधार के भी सुझाव दे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जितनी ये कमाऊ खाऊ संस्थाएँ हैं ये ही सारा रुपया हड़प कर जायेंगी और हरिजनों के कल्याण का कोई काम नहीं होगा।

श्री तु० रा० (अरावली) : शैड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर का रिपोर्ट पर बहस हो रही है बहस के दौरान में हरिजनों और नान-हरिजनों ने भी बहुत से सुझाव दिए हैं। समय कम है और बातें कहने को बहुत ज्यादा हैं। इसलिए मैं मुख्य-मुख्य बातों की तरफ ही आपका ध्यान आकर्षित करूंगा।

हमारे नेता सोचते थे स्वराज्य के पहले और स्वराज्य के बाद भी कि हरिजनों

के ऊपर सामाजिक, आर्थिक और राज-नीतिक अत्याचार हुए हैं और उन अत्याचारों के कारण वे इतने पीड़ित हो गए हैं कि उनको शकल मनुष्य की तो है लेकिन उनको स्थिति जानवरों से भी बदतर है। इस वास्ते संविधान में कुछ विशेष सुविधायें हरिजनों और आदिवासियों को दी गई थीं। लेकिन बीस साल में जो सुविधायें दी गई हैं वे अपर्याप्त ही सिद्ध हुई हैं और इन वर्षों में जो फंड इनकी भलाई के लिए मुहैया किये गये हैं उनका या तो पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ और अगर हुआ भी है तो गलत इस्तेमाल हुआ है। हरिजनों को आगे बढ़ने में जो कुछ किया जाना चाहिये था इन फंड्स की सहायता से नहीं किया गया। क्योंकि इतना गलत इस्तेमाल हुआ? इसका कारण यह है कि हमारे जो नेता लोग हैं और जिनके माध्यम से यह काम करवाया जा रहा है उनके दिलों और दिमागों में यही बात है कि इन वर्गों के ऊपर वे दया कर रहे हैं। हम भी यही समझ रहे थे कि यह दया वाली बात है। जो दे दें सो ले लो। लेकिन स्थिति यह नहीं है। यह मर्जी और दया की बात नहीं है। यह दम करोड़ आबादी की बात है, उन आबादी की बात है जिसको हालत बहुत ही बदतर है, जिसको सामाजिक स्थिति बहुत ही खराब है।

यह कहा जाता है कि असुविध्यता का अन्त हो रहा है। हो सकता है कि यह बात जहां तक शहरों का सम्बन्ध है, कुछ हद तक सही हो। लेकिन देहातों में आप जायें, गांवों में आप जायें तो आपको छुआछूत वैसे ही देखने को मिलेगी जैसे पहले मिला करती थी। आप जानते ही हैं कि हिन्दुस्तान शहरों का देश नहीं है। हिन्दुस्तान गांवों का देश है। गांवों के अन्दर वही स्थिति आज भी है जो पहले थी। मैं एलानिया तीर पर कहता हूं कि सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले जितने

[श्री तु० राम]

भीनेतागण हैं चाहे वे इस पार्टी से सम्बन्ध रखते हों या उधर वालो किसी पार्टी से सम्बन्ध रखते हों, जो उन्होंने सामाजिक क्रान्ति लाने के प्रयत्न पहले किये थे उनमें अब ढील आ गई है। इसका कारण वोट का डर है। हम लोग बीकर सैकशंज आफ सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं। हम में राजनीतिक चेतना अभी जागी नहीं है। हम में जागृति पैदा नहीं हुई है। जो कुछ कोई कह देता है उसपर हम लोग विश्वास कर लेते हैं। जो गांवों के अन्दर अत्याचार कर रहे हैं वही वोट्स कमांड करते हैं, वही जिधर चाहते हैं वोट दिला देते हैं। इसमें समाजवादी आचरण भी नहीं रह जाता है। जितने भी इलैक्शन लड़ने वाले लोग हैं, चाहे वे कांग्रेस पार्टी के हों या अपोजीशन पार्टीज के हों, जो भी पार्लियामेंट के लिए या असम्बलो के लिए इलैक्शन लड़ते हैं उनमें सैक्रिफाइस की भावना नहीं रह गई है, जो भावना उनमें पहले हुआ करती थी अब नहीं है। सभी राजनीतिक पार्टियों में यह कमजोरी आ गई है। जिस रफतार से एक समय में क्रान्ति हिन्दुस्तान में चलती थी आज वह नहीं चलती है। उपाध्यक्ष महोदय, मूल रूप से हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या है आर्थिक और सामाजिक। लेकिन आर्थिक समस्या की ओर हमारा झुकाव नहीं होता। मैं देखता हूं कि एक आदत सी बन गई है जब तक आन्दोलन नहीं किया जाता है, जोर नहीं दिया जाता है तब तक सुनवाई नहीं होती। नक्सलवाड़ी में कुछ गड़बड़ हुई तो कहते हैं कि भूमि की भूख जगी है और उनको भूमि दो। और विनोबा जी को भी प्रेरणा कहां से मिली थी? कम्यूनिस्टों ने तेलंगाना में आन्दोलन किया था। वह गलत दिशा में कम्यूनिस्ट लोग ले गए। लेकिन विनोबा जी ने प्रेरणा वहीं से

ली थी। 'इन' वर्गों को प्रेरणा कहां से आई? तो कहा है:

भूखे भजन न होय गोपाला।  
ले लो अपनी कंठी माला ॥ और  
वह क्या जाने पीर पराई,  
हलुआ पूरी खाते हैं जो।  
हानों कैंसी तड़प भूख की,  
माहन भोग उड़ाते हैं जो ॥

आज उसी सन्दर्भ में जो हमारी दिक्कतें हैं वह मैं सामने लाना चाहता हूं। आखिर जो हम ने टागेट्स लिए उन टागेट्स को पूरा नहीं करने का कारण क्या है? कारण है, हम नेताओं में भी आज ढिलाई है और जो हमारी काम करने वाली मशीनरी है उस में भी ढिलाई आई है। और इस ढिलाई आने का नतीजा यही होगा, गलत दिशाओं में हरिजनों को लोग ले जायेंगे क्योंकि जो समाज विरोधी तत्व हैं जिसका खतरा है आप को चीन का और पाकिस्तान का वह इस का फायदा उठाएंगे। कहा जाता है कि नक्सलवाड़ी में लोगों को उकसाया गया। लेकिन मेरा पेट भरेगा, हम को सामाजिक आजादी मिलेगी तो गलत दिशा की ओर हम अपना कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन हम भूखे रहते हैं, हमारे ऊपर अत्याचार होता है तो किसी के बहकावे में आकर नाजायज काम भी कर बैठते हैं। समय ज्यादा नहीं है मैं व्योरेवार कहना चाहता था।

आज क्या हालत है? कहा जाता है है अछूतोंद्वारा करने के लिए मंदिरों को खोलो। अरे बाबा मन्दिरों को मत खोलो। मन्दिर अपने बन्द रहने दो, पत्थर की मूर्तियों को कैदखाने में पड़ा रहने दो। हमारे लिए तो ज्ञान का मन्दिर खोल दो। हम खुलवा लेंगे मन्दिरों को और मस्जिदों को। हम देख लेंगे धर्म के ठेकेदारों को। जब तक रूहानी ताकत

नहीं आयेगी संरक्षण से और कनून के बल पर से जो समाज के अन्दर अन्धविश्वास है उस पर हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमारे लिये ज्ञान का मन्दिर खोलने का क्या मतलब है ? हरिजन सेवक संघ या और गैर-सरकारी संस्थाओं के माध्यम से जो पैसा खर्च कर रहे हैं, 20 साल का, 26 साल का अनुभव बता रहा है कि उन का गलत इस्तेमाल किया गया। उन रुपयों को कहीं हरिजन हास्टेल खुलवाने के नाम पर और कहीं किसी नाम पर खर्च किया गया। यह भी मैंने सुझाव दिया इस के पहले कि इस से पृथक्ता की भावना आ रही है। आप चाहते हैं कि हरिजनों को हरिजनों के रूप में देखना ? अगर हरिजनों को हरिजन के रूप में ही देखना चाहते हैं तो दूसरी बात नहीं तो मनुष्य मनुष्य है यह समझ कर के और वर्ग-विहीन और वर्ण-विहीन समाज की स्थापना चाहते हैं तो फिर आप को आमूल परिवर्तन करना होगा एजुकेशन में। यह क्या हरिजन छात्रावास बना रहे है ? हरिजन छात्रावास क्या ? क्या हरिजनस्तान बनाना चाहते हैं ? हरिजन छात्रावास का क्या मतलब ? आप जनरल हास्टेल में इस वर्ग के लड़कों को जगह दीजिए और पूरा का पूरा खर्च दीजिए तब तो संस्कृति का आदान प्रदान हो सकेगा नहीं तो कूड़े करकट को हरिजन छात्रावास में आप ने रख दिया, जिनके बाल बच्चों को पढ़ने की आदत नहीं थी, जिन को इस प्रकार से रहने की आदत नहीं थी, जिनको मनुष्य के रूप में समझा नहीं जाता था उन को आप ने वहां रख दिया तो उस से संस्कृति का आदान प्रदान क्या होगा ? इस तरह तो एक हरिजनस्तान आप बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि जनरल तरीके से जहां सबर्ण और ऊंची जाति के लड़के रहते हों वहीं उन को रखा जाय। पचास बह रहे, पचास यह रहें जिस में हीनता की भावना उन के अन्दर न आये। जब तक हम हीनता की भावना

को खत्म नहीं करेंगे तब तक इस समाज का कल्याण नहीं कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि रेकमेंडेशन पर रेकमेंडेशन हो रही है, सिफारिशें हो रही हैं। यह तो वैसे ही सिफारिशें हो रही हैं जैसे हमारे धर्म के नेता लोग भी बहुत सी सिफारिशें कर गए कि जीवात्मा को तकलीफ मत देना। दूसरे को सताना नहीं किसी दूसरे मजहब वाले को सताना नहीं लेकिन हमारे पंगम्बरों, हमारे ऋषियों, महर्षियों की भी वाणी नहीं रही वैसे ही करोड़ों और लाखों रुपया खर्च करके रिपोर्ट तैयार की जाती है सिफारिश की की जाती है। लेकिन मुश्तदी के साथ उस सिफारिश पर अमल नहीं किया जाता, सिर्फ वाद-विवाद के लिए एक रस्मी तौर पर यहां पार्लियामेंट के टेबल पर लाया जाता है न कि कार्यान्वित करने के लिए जो इस के अमूल्य सजेशन हैं, इस की बहुमूल्य सिफारिशें हैं उन पर अमल किया जाय। हम ने देखा है बहुत सावधानी से देखा है इन की रिपोर्ट को। उन लोगों ने मेहनत की है। लेकिन मैं आप को बताऊं मैं कहां से आता हूं ? मैं पूर्णिया से आता हूं। जहां पर लोगों को कोसी ने कालाजार और न्योमोनिया से बरबाद कर दिया। रेगिस्तान पड़ा है। लेकिन अब भी लाखों लाख एकड़ जमीन सरकार की बची हुई है। मगर 20 साल से एक मामूली सी समस्या भी हमारी हल नहीं कर सके कि इतनी जमीन गरीब हरिजनों को दे सकें जिस में कि वह शोपड़ी बनाकर रह सकें। शोपड़ी के अंदर रहने लायक जमीन भी नहीं मिल सकी। लाखों लाख एकड़ जमीन पड़ती पड़ी हुई है और सरकार कहती है कि अन्न उत्पादन करो।

मैंने देखा खास कर के मुसहर जाति को जिस की बस्तियों में आप जायेंगे तो 500 औरतें जो आप के सामने आयेंगी

[श्री तु० राम]

उन में दो चार को तो शायद आप देखेंगे कि उनकी साड़ी फटी न हो, नहीं तो सी सी चियड़े लगे हुए होंगे और पांच पांच, सात सात साल, आठ आठ साल के बच्चे, चाहे वह लड़के हों या लड़कियाँ वह नंगे आप के सामने आयेंगे। और खाने के लिये क्या है? आठ आने मजदूरी। मुझे उस मुम्हर्नी ने बताया था। इस महंगाई के जमाने में भी बड़े बड़े जमींदार और पूँजीपति दो दो हजार बाघा जमीन जोतने वाले जो धर्म के ठेकेदार हैं वह आठ आने मजदूरी दे कर हमारी लाचारी और विवशता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने मुझ से कहा कि क्या वह दिन आयेगा कि जब हम को 1 रुपये और 2 रुपये मजदूरी आप दिला सकेंगे? मैंने कहा कि मैं तुम्हारे सवाल को पार्लियामेंट में रखूँगा, देश के नेताओं के सामने रखूँगा। तो मैं आप से अपील करना चाहता हूँ और आप के माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि बहुत दर्दनाक स्थिति है। और अब वह समय आ गया है कि बदलती हुई राजनीति की पृष्ठभूमि में है। गंभीरता से इस समस्या का समाधान करना होगा तब तो शांति रहेगी। नहीं तो जो क्रान्ति का विप्लव आने वाला है, सत्यानाश का उस में हमारा और समाज का सब का सर्वनाश हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

**Mr. Deputy-Speaker:** The hon. Minister.

**Shri C. Chittybabu:** Sir, may I submit . . .

**Mr. Deputy-Speaker:** Your party has taken 32 minutes. I am sorry, I cannot extend the time any more. It

is very difficult. Kindly excuse me . . . (interruptions)

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** उपाध्यक्ष महोदय, मुझ भा टाइम मिलना चाहिए।

**Shri C. Chittybabu:** Sir, you promised me an opportunity.

**Mr. Deputy-Speaker:** It is not a question of any promise.

**Shri C. Chittybabu:** You have given 15 minutes and 20 minutes to others but you are denying me an opportunity.

**Mr. Deputy-Speaker:** The member who concluded his speech just now said that he will take only 3 minutes. But, while he was speaking, other Members encouraged him to take more time. It is not fair. In that way, it is not possible to give opportunity to others.

**Shri V. Krishnamoorthi (Cuddalore):** He is asking only for ten minutes.

**Mr. Deputy-Speaker:** I will give him 3 minutes. Please resume your seat. Nobody finishes in five minutes. It is a question of some time limit, some end of a debate. We have extended the time twice. How is it possible to extend it further?

**Shri C. Chittybabu (Chingalaput): \***

**Mr. Deputy-Speaker:** Sir, I am ashamed that persons belonging to the ruling party have spoken in great hurry about the problem of the backward sections of people. The speeches which ought to have been made by us, who sit in the opposition, have been made by them. I am really ashamed that the members of the ruling party have themselves broadcast to the whole world that poor peo-

pie have been made to remain backward people in this country. When it is found that members of the Congress party are making speeches which ought to be made by us, the doubt arises whether there was Congress rule in this country for twenty years. We are not able to understand how far the Government have implemented the schemes which it has drawn up fourteen times. Members of the Congress party have spoken that the schemes for ensuring the welfare of the backward sections of society have not been implemented. We are not only surprised that all the parties are agreed on this issue, but that it is an indication of the achievement of the Congress Government in this regard. It is amazing that members of the Congress party have pinpointed to the world the failures of the Congress ministers in this regard. I want to refer to one matter here. In Madras many huts were destroyed by fire and when Shri Annadurai, Chief Minister of Madras, asked for funds telegraphically, Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi gave Rs. 50,000. But when the Deputy Prime Minister Shri Morarji Desai visited Madras and when he addressed a mammoth public meeting, he did not say a word of consolation to the backward class people who were affected by those fires. On the other hand, he spoke disparagingly of the scheme to give them doles. I ask a straightforward question. The Deputy Prime Minister is not able to say a word of consolation to the backward people who were homeless and were on the streets. But he is able to ask . . . (Interruptions). But he is able to ask whom "Anna's" regime has helped.

The labourer working in a shop has at least a shop act. But the Government is not able to help the person who works in the field. I consider it my duty to ask that an agricultural scheme should be brought forward for his protection.

Reference has been made that there is untouchability among the backward

class people. What is its reason? There is casteism in the country. What has been done by you to abolish it? What opportunities have you provided for inter-caste marriages? Is the Government prepared to encourage inter-caste marriages and to settle one person belonging to the backward class by the side of each house in the 'Agrahara'? I also ask whether Congress is prepared to seat a person belonging to the backward class in the place of the Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi? When there was a contest for the office of President this Government was not ready to sponsor a person belonging to the backward class as the Congress candidate. But the country is watching the manner in which you are helping the backward class people. There is only one way to remedy the situation. People from all sections in the country should unseat Congress from the pedestal of power at the Centre. Unless this is done, I assert most emphatically in this House the welfare of backward class people cannot be ensured. I thank you for the opportunity provided to me.

**Mr. Deputy-Speaker:** The hon. Minister.

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने का मौका दीजिये।

**Mr. Deputy Speaker:** Please resume your seat; not a minute now.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मानने मुझे कल से आश्वासन दिया हुआ है, मैं तब से बराबर बैठा हुआ हूँ।

**Mr. Deputy-Speaker:** I appeal to group leaders. I have given more time to your group. This is not fair.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मानने मुझे कल से आश्वासन दिया हुआ है।

[श्री हुकम चन्द कछवाय]

आज भी आप ने कहा था कि मौका देंगे, अब मुझे बोलने का मौका देना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं मिलेगा।

श्री हुकम चन्द कछवाय : आप ने श्रीरों को दिया है, मुझे भी दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका टाइम खत्म हो गया है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : टाइम तो कांग्रेस का खत्म हुआ है, हमारा टाइम खत्म नहीं हुआ है। आपने हम को कितना समय दिया है? आपने समय से ज्यादा कांग्रेस पाटा को दिया है, उन का समय समाप्त हो गया है। हमें आप बोलने दीजिये, हमें बोलने के लिये समय देना पड़ेगा।

An hon. Member: Let him be given an opportunity.

Mr. Deputy-Speaker: It is not possible. Your party's time is over and now you plead for someone else to speak. How can you control the House like this? Do you want to have the debate indefinitely? There must be some limit. I appeal to party leaders. Every group leader is trying to encourage someone. This is unfair.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मेरे लिये आप ऐसी बात करते हैं, दूसरों के लिये नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी के सब लोगों को आपने बुलवाया, कल जितने लोगों ने वाक आउट किया, उन सब को बोलने दिया। आप मुझे भी पांच मिनट दीजिये।

The Minister of Planning, Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am grateful. . .

श्री हुकम चन्द कछवाय : आप मुझे पांच मिनट दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको वक्त नहीं मिलेगा।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं वाक आउट करूँ, उपाध्यक्ष महोदय।

Mr. Deputy-Speaker: That is for you to decide.

श्री हुकम चन्द कछवाय : आप पक्षपात क्यों करते हैं, उपाध्यक्ष महोदय। आप कांग्रेस के बाँट से चुन कर आये हैं, इसीलिये ऐसी बात करते हैं।

Mr. Deputy-Speaker: There is some limit to a debate. I extended the time thrice. Even though the Speaker announced that the Minister will be called at 2 O' Clock, I extended the time again. I tried to accommodate some Members.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं कल से लग-तार बँठा हुआ हूँ। मैंने कल भी निवेदन किया था। कल आपने आश्वासन दिया था और मैं इन्तजार में बैठा रहा, तान-तीन चिट्ठियाँ आपको मैंने लिखीं, फिर भी आप मुझे मौका नहीं देना चाहते हैं।

Mr. Deputy Speaker: The hon. Minister may continue his speech.

Shri Asoka Mehta: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am grateful to the hon. Members. . . .

श्री हुकम चन्द कछवाय : कांग्रेस के वोट से चुन कर बैठे हो, इस लिये धीस से बैठाना चाहते हो।

Shri Asoka Mehta: I am grateful to the hon. Member. . . .

श्री हुकम चन्द कछवाय : उपाध्यक्ष महोदय, आपको समय मुझे देना होगा।

**Mr. Deputy-Speaker:** It is not possible. I appeal to the group leaders. If you continue like this, I will have to take action.

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** आपने आरोपों को बुलवाया है, मुझे समय क्या नहीं देना चाहत है ।

**Mr. Deputy-Speaker:** There must be some discipline, some order, in the House. There is another Member on this side also who wants to speak. I have got seven chits with me.

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** यह अनुशासन मेरे लिये हो है क्या ? कांग्रेस के लोगों के लिये नहीं है ।

**Mr. Asoka Mehta:** I am grateful to the hon. Members who have participated in this discussion. I am also grateful to them for the very valuable suggestions they have made. . .

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** कल जब समय बढ़ाया गया—उधर के लोगों ने वाक-आउट किया था, इसलिये समय बढ़ाया गया । कल मेरा प्रस्ताव भी था कि दो घण्टे समय बढ़ाया जाय, तब अपने मुझे कहा था कि मुझे भी बोलने का मौका देगे ।

**Mr. Deputy-Speaker:** There should be some limit to it. You ought to realise it. Yesterday, your party representative came here and represented and, though the time of your party was exhausted, I gave a few minutes. May I read out that here?

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने दें ।

**श्री रामगोपाल शाल वाले (चन्द्रती चौक) :** जब दूसरों को समय दिया है तो उन को भी दिलका दोजिये । इतने समय में तो वे बोल लेते ।

**Mr. Deputy-Speaker:** I will not give him a second.

1884 (Ai) LSD—9.

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं । हम देखते हैं कि आप किस तरह से कार्यवाही चलाते हैं । आपने मुझे बुलवाने का आश्वासन दिया था ।

**Shri Asoka Mehta:** I cannot speak when the other gentleman is also speaking. I can continue only if the House is interested in my reply. I have no desire to continue if the other gentleman also goes on speaking.

**Shri Sheo Narain (Basti):** On a point of order.

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** आप मुझे पांच मिनट दाजिये । आपने मुझे इस का दो बार आश्वासन दिया है । कल भी दिया है और आज भी दिया है ।

**Mr. Deputy-Speaker:** I will not give.

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** आप ने कहा था कि मुझे बोलने का समय देंगे इसलिए आप अपने आश्वासन को पूरा कीजिये और मुझे भी बुलवाइये ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब और किसी को भी चांस नहीं दिया जा सकता था । मिनिस्टर साहब को बुला लिया गया है और वह बोल भी रहे हैं ।

**Shri Asoka Mehta:** I am grateful to the hon. members of this House who have participated in this discussion and who have made very valuable suggestions. . . .

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** आप ने कल भी आश्वासन दिया था और आज भी दिया है । मैं शैंड्यूल्ड कास्ट का हूँ मुझे मीका दिया जाय ।

**Mr. Deputy-Speaker:** He came here and I told him that his Group had taken more time than what was allotted and that, if we extended further, if we could accommodate, we would see. Nobody finishes his speech in five minutes. I received slips from persons belonging to Scheduled



[Mr. Deputy-Speaker]

Castes and Scheduled Tribes. They have legitimate grievances. I tried to accommodate every one from this side as well as from that side. But henceforward it is not possible.

**श्री जगन्नाथ राव जोशी (भापाल) :**

यह 2 घंटे इतने पर समय बढ़ाने का प्रस्ताव श्री कछवाय ने ही किया था इसलिए पांच मिनट का समय इन्हें दे देना चाहिए।

**Mr. Deputy-Speaker:** Mr. Joshi, it is not fair. If he cannot control his Party-man, it is for him to decide as to what he should do.

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप मुझे नहीं बुलायेंगे। यह जो दो घंटे बढ़वाये थे वह इसलिए बढ़वाये थे कि जो लोग बोलने से रह गये हैं उन्हीं लोगों को बुलाया जायगा और उस में मैं भी शामिल हूँ.....

**Mr. Deputy-Speaker:** Can we allow this defiance? There must be some limit... (Interruption). There is no point in conducting the House like this. He will please resume his seat.

**श्री जगन्नाथ राव जोशी :** पांच मिनट इन्हें दे दें।

**Mr. Deputy-Speaker:** Mr. Joshi, shall I take the extreme step? Shall I name him? (Interruptions). We have tried to accommodate him on every occasion. This is not fair. Mr. Joshi may ask him to voluntarily withdraw or....

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** आप मुझे नहीं बुलायेंगे? तब मुझे दो बार आश्वासन क्यों दिया था? आप मुझे धीरे देते हैं धीरे में मुझे रखना चाहते हैं?

**श्री जगन्नाथ राव जोशी :** क्या पांच मिनट का समय नहीं दिया जा सकता है?

**Mr. Deputy-Speaker:** Will he believe me? Mr. Chakrapani is there. His representative came. I said that, time permitting, I would accommodate all. Beyond that, I have said nothing. The hon. Minister may continue.

**Shri Asoka Mehta:** I am grateful to the hon. members of this House who have participated in this discussion and who have made valuable suggestions....

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** मेरे ऊपर धीरे जमाते हो। क्या वह 2 घंटे इसलिए आप ने बढ़ाये थे?

**Mr. Deputy-Speaker:** Will Mr. Madhok do something about him? I do not want to take the extreme step.

**Shri Asoka Mehta:** I can understand the indignation and anger....

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** उपाध्यक्ष महोदय, तो आप मुझे नहीं बुलायेंगे। देखूंगा कि आप कैसे कार्यवाही चलाते हैं?

**Shri Sheo Narain:** He should be named.

**Shri Asoka Mehta:** I can understand the indignation and anger that some members have felt....

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** यह दो घंटे मैंने उन से लड़ कर बढ़वाये थे और मुझे ही उन्होंने नहीं बुलाया।

**Shri Asoka Mehta:** I can very well understand the indignation and anger felt by some hon. members. (Interruptions). The fact that indignation and anger were expressed is itself an indication of the awakening and the strength that this segment, 110 million people, have gathered for themselves.

Some hon. members pointed out that there had been some change in the motion that we had tabled; while in the past the motion used to be "That the House takes into con-

sideration this Report. . .", now it is, "That this House takes note of the Report. . .".

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या यह दो घंटे आप ने इसा लिए बढ़ाये थे कि उधर के तो सब लोगों को बोलने दिया और मुझे को बोलने नहीं दिया ?

**Shri Asoka Mehta:** The reason for the change has been that the Secretariat of Lok Sabha had suggested to us that it might be better to use the expression 'takes note of' rather than 'takes into consideration'. If the hon. Members desire that we should use the expression 'takes into consideration', we shall not have the slightest objection.

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** मैं गैड्यूल्ड कास्ट का हूँ। मैंने ही यह दो घंटे का समय बढ़वाया और मुझ ही पांच मिनट का समय भी आप बोलने के लिए नहीं दे रहे हैं। देखूंगा कि आप कैसे कार्यवाही चलाते हैं।

**Shri Asoka Mehta:** I am aware of the fact that in the past there had been some delay in presenting the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes before the House. But this time we have made every effort to see that the earlier delay is eliminated. I would like to assure the House that the next report of the Commissioner would be placed on the Table of the House during the next budget session we hope that every year the report will be presented to the House at the time of the budget session. I am sure hon. Members have also noticed that the report has been organised in a somewhat more meaningful manner and this process of organising the report in a manner whereby the House will be able to draw the maximum benefit will be continued.

It has been said that in the past there was the practice of laying on the Table of the House or circulating a note embodying the various steps taken by Government to implement

the recommendations made by the commissioner and that on this occasion it has not been done. That is not a fact. The report for 1964-65 contains a detailed note about the steps that were taken on the earlier reports. As for the two reports that the House is discussing, it is not yet possible for Government to say what steps will be taken, because the final steps are taken only after taking into account the discussions that take place in this House as well as in the other House. But, here again I would like to assure the House that a brief report on the steps taken by Government on the various recommendations will be placed before the November-December session of Parliament this year, as well as in future. On both these points, namely the regularity of submitting the reports and the regularity of submitting a note on the steps taken, I can assure you that the time-table that I have indicated will be adhered to.

Then, a number of hon. Members have suggested that there should be a committee of Parliament of both Houses, a small compact committee which should look into the recommendations made by the Commissioner and generally be able to advise and guide the Department of Social Welfare in the onerous responsibilities that have been entrusted to it. I welcome the suggestion. But I would beg of those who have moved various amendments not to press those amendments, because I accept the suggestion that such a committee be set up. But what the exact shape of the committee should be and what precisely should be the nature and character of the committee has to be decided in consultation with the Speaker and perhaps the Chairman of the other House also. Therefore, I would request those hon. Members who have moved amendments that they need not press their amendments, because the suggestion has been accepted and I hope that such a committee will be set up in the near future.

**Shri Bal Raj Madhok** (South Delhi): May I make one suggestion? In these matters I find that people think that it is only the concern of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I would submit that it is the concern of the whole country.

**Shri Asoka Mehta**: That is one of the things that I have to discuss with various people. I would like to the committee to be a small and compact one. Of course, the representatives of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes will be there, but there will be others also. I hope some of the leaders of the various parties will also join the committee so that it may be able to give maximum support to the implementation programme that we want to put through.

It has been suggested that some resolutions be adopted. I am afraid it is not possible for this House to adopt any resolution on the Commissioner's report, because apart from the Commissioner's report, we have some advisory committees, and we also have to consult the States, and decisions have to be taken after taking into consideration a variety of facts and factors.

Another suggestion has been made that there may be a single Ministry to look after all the problems and all the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I wish it were possible to set up such a Ministry, but I am afraid it is not a feasible proposition. Matters pertaining to education will inevitably be dealt with by the Education Ministry, matters concerning agriculture must necessarily be dealt with in the Agriculture Ministry and so on and so forth. It is just not possible to have all these matters brought within the purview of one single ministry or department. Let us also realise that a large number of State Governments are also concerned with these matters. Therefore, what we are trying to do is to co-ordinate these

various activities and efforts as closely as possible.

I can assure you that all that has been discussed here and the various suggestions made have already been conveyed to, and have been carefully considered by, the Prime Minister, the Deputy Prime Minister, the Home Minister and other colleagues of mine concerned. Many members belonging to the scheduled castes and scheduled tribes have expressed their dissatisfaction about the inadequacy of representation, not only in the services, but in various high political positions in the country. On this point also, I do not think it is necessary for me to point out that the Prime Minister and the Home Minister who are present here as well as other colleagues of ours in Government are fully aware of the deep feelings among the scheduled castes and scheduled tribes, the legitimacy of their aspirations and have a keen desire to respond to these aspirations and to meet them to the best of our ability.

I would further point out that yesterday my colleague the Minister of State in the Home Ministry gave a detailed analysis of what is being done to provide employment opportunities to persons belonging to the scheduled castes and scheduled tribes in government service, as well as outside. As he pointed out, we have set up a small group in which the Home Minister and I are taking very keen interest and I would like to assure the House on behalf of himself and myself that we are going to pursue this matter in a very determined manner in the coming months not only in the government services, but in other services also. It is our desire and determination to see that the legitimate rights and aspirations of this 21 per cent of the Indian people are fully met and satisfied.

The 1965-66 Report has made 131 recommendations. As to what steps have to be taken about them, what

follow-up action has to be taken, I have got all these things worked out here, but it is not possible for me to indicate these things just now till I have held further consultations with the members themselves, as well as the privilege and opportunity of knowing from the House and the other what they have to say about it.

As far as education is concerned, I realise that for that for these 110 million people belonging to the scheduled castes and scheduled tribes all that needs to be done has not been done. Let us realise that Indian is a very large country, a very poor country, and the changes we are trying to make and the transformation we seek to achieve cannot be brought about at a speed and in a manner which would satisfy all of us. But may I point out that if we look to what we have been doing for providing educational facilities to the young men and women of these communities, we will find that the provision for education has been increased four-fold from the First Plan to the Third. As regards the provision made for post-matric scholarships, it has been increased nine-fold between the First and Third Plans.

My very good friend, Shri S. M. Joshi, was rightly indignant about the condition of the scheduled castes and scheduled tribes. I share his sense of sorrow, frustration and indignation, but we must realise side by side what is being done. Today there are a hundred thousand students belonging to these communities studying in universities. 35 years ago when Shri Joshi and I—were students in Bombay University, what was the total number of students in those days studying in the universities? The number was only slightly more than 100,000 or 120,000 the number that we are having today belonging to the scheduled castes and scheduled tribes alone. I am talking only of university students. Did we feel at that time that we were completely

neglected? Did we feel that we did not have within us the strength and the power to change the world? You and I and Mr. Joshi, when we were part of the 100,000 or 120,000 students studying in the universities, we felt that we had within us the competence, the confidence, the strength to work out a certain scheme of things and rebuild our country nearer to our heart's desire. I say today that from amongst the 110 million scheduled castes and scheduled tribes people there are the same number (100,000) of young men and women studying in the universities, and it is out of their strength, and confidence, that a new social order is going to be created. So, while we should recognise that a lot has still to be done, we must not underrate what has already been done.

Let us look at this question of providing land to the landless people.

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** उन को पढ़ने के बाद नीकरा नहीं मिलती ।

**Shri Asoka Mehta:** I have listened for nine hours without once opening my mouth.

I realise that there is a tremendous land hunger. I realise that the number of landless people among the scheduled castes is almost 100 per cent more than among the rest of the population. Having realised that, I must point out that during the last 15 years about 10 million acres are reported to have been distributed to landless agricultural workers, out of which about 3.91 million acres or 39 per cent had been allotted to the scheduled castes and scheduled tribes. Forty-five per cent of the total number of beneficiaries belong to the category of scheduled castes and scheduled tribes. I do not want to take too much of your time on this point.

It is often said that the people are not getting their scholarships in time. I agree, that may be happening, but let us realise that over six lakhs

[Shri Asoka Mehta]

scholarships have been given in the last 15 years. Out of these six lakhs, even if one or two or five per cent do not receive the stipends in time—of course, it is something to be corrected, it is something which is unfortunate—what about the 95 per cent of the people or more who have received it in time? Otherwise, how do these figures come up? How is it that there are hundreds of thousands of students today who have matriculated graduated, who have achieved the highest educational qualifications that any one can aspire to? Therefore, while I shall always welcome all suggestions, all information that indicate aberrations in our efforts at implementing things, I would beg of the House to realise that ultimately all these things have to be viewed in the correct perspective.

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** जो मंत्री आता है, आश्वामन देता है लेकिन होता कुछ नहीं है। इस बीस साल में कुछ भी नहीं हुआ है।

**Shri Asoka Mehta:** The next point to be realised is that as far as the scheduled tribes are concerned, tribal blocks have been set up, and 120 lakhs of tribal population are covered by these blocks. Something like Rs. 16 or Rs. 18 crores have been spent on them. We want to cover about a crore more of people, if possible during the current plan period or at least during the next five years, and that would cover the bulk of the tribal population.

There are, however, two difficulties which must be realised. The first difficulty is that the finances that are made available for special programmes for scheduled castes and scheduled tribes are in the nature of supplementary provisions, and they must not be treated as substitutes for the share that should go to the scheduled castes and scheduled tribes from the general development programmes.

Unfortunately, this does not always happen. In State after State, in district after district, in panchayat after panchayat there is a tendency to use them as substantive provisions.

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** इस का दोषी कौन है ?

**Shri Asoka Mehta:** The opposition parties are also in power, and when they look into the functioning of their own States, they will find that these difficulties are there that arise out of our social structure. To change that social structure is necessary, but the social structure is not going to be changed merely by talking about blowing it up. Here is a social transformation, which is necessary, and I am sure Mr. Joshi, Mr. Madhok, and Mr. Dange understand its implications as much as Mr. Chavan or I do. Therefore merely showing anger is no good. Anger is meaningful if it is dynamised for changed, but it has no meaning if it is merely an effervescence all the time. Therefore, I would like this Parliamentary committee to be appointed to help the Department of Social Welfare in seeing that the special provisions made for scheduled castes and tribes are treated as supplementary provisions and are not treated as substantive provisions.

Secondly, our economy is passing through very difficult conditions. With the limited resources available, the first claim is made by agriculture or productive schemes and social services invariably tend to suffer. No matter which particular party is in power, I am prepared to throw out a challenge that there is not a single State Government today which has provided as much for social welfare or for the welfare of the backward classes this year as they did last year. Not because they have no desire to do it; but when resources shrink a certain priority has to be observed.

. . . (Interruptions.) No matter

even if the most critical gentlemen sit down tomorrow and decide priorities, they will find that productive efforts have to be given a certain higher priority than welfare because welfare services need wealth to be generated and if the generation of wealth suffers, you cannot create the services needed for welfare.

I realise twenty years are over. But I can assure the hon. Members that we should not look at the future in terms of the past; that would be a telescopic mis-adventure. Potentialities for growth have been built up and in the future, our movement and our progress will be faster. But that does not mean that dissatisfaction will be less. I can envisage growing dissatisfaction in the next twenty years. Dissatisfaction occurs only when people are educated and people are trying to improve themselves.

I would also like to say just one word to Prof. Swell. He allowed himself to be carried away by a certain inflammatory speech made by an hon. member on the opposite side. But he should realise that after all if he and his friends are to live peacefully and happily in Assam, the people of the hills and the people of the valley must live together and work together and there must be a certain amount of understanding between them. . . . (Interruptions.) I did not interrupt you when you were speaking; you can ask me a question at the end if you like.

**Shri Swell (Autonomous Districts):** We never say we want to live peacefully within Assam; we say we want to live peacefully within India.

**Shri Asoka Mehta:** If you have to live in peace, give us two months in which we will try to evolve a consensus. Is this something of a betrayal of the plighted word? After all the Government can carry out their word only in context of an atmosphere of goodwill. Would Prof. Swell like it when something is imposed upon him,

and upon his patriotic colleagues? He would like that he should be persuaded, he should be brought round to the acceptance of whatever is being proposed by mutual exchange of ideas and understanding. Is it too much to ask that two months be given to bring around the 10-12 million people living in Assam? They have waited patiently, I admire their patience. I admire the goodwill with which my friends from the hill districts have waited. If we request them: give us two more months in which a final solution may be searched, which would receive the ready acceptance of the people of Assam, is it betraying the plighted word? Is it necessary to turn round and say that this will happen and that will happen? We are fully aware of the strength and the weaknesses of every section of our people. This Government is not interested in exploiting the weaknesses of any section, this government is anxious to mobilise the strength of every section of our people. Let me assure Prof. Swell that if we have asked for two months, these two months have been asked for in order that the final solution that is proposed is capable of readier and more responsible implementation than would be the case if the Home Minister were to issue a fiat tomorrow I would again, through Prof. Swell, convey to his colleagues that the greater the co-operation they extend to us during the next two months, the better and the greater will be our ability to help them in solving the difficult and very important problems in that part of our country.

Lastly, I would like to thank all the hon. members for the very valuable suggestions they have made. Let me assure them that we shall give them the fullest consideration. If the Prime Minister would agree to have a scheduled caste or scheduled tribe person as Minister in charge of the Department of Social Welfare, I would be very happy. But so long as I am in charge of this department,

[Shri Asoka Mehta]

I can assure them that I shall not be found wanting in trying to meet their legitimate aspirations and I shall always be ready to gain in understanding and insight by the wisdom and experience that they possess.

**Shri Swell:** Sir, I appreciate the sentiments and the righteous indignation of my esteemed and respected friend and colleague, Mr. Asoka Mehta. But I would like to put the record straight. Our case has never been that we want to live within Assam. Our case is that we want to live within India as equal, trusted partners of this great country. That is a big difference. Mr. Asoka Mehta has referred to a period of 2 months. I understand that. But my understanding was that it is no longer two months now; it is just 3 weeks. May I know whether there has been any further revision in the mind of the Government with regard to the time-limit of 31st August, which is set?

**Mr. Deputy-Speaker:** I allowed your question, but I do not want to continue the debate. If I allow him to reply to your question, other questions will be there and it will be another debate.

**Shri Swell:** It is a very pointed question, Sir.

**Mr. Deputy-Speaker:** You should understand my difficulty. We must put an end to this debate somewhere at some time. How long can it be continued?

**Shri Bal Raj Madhok:** Let him assure that he will write to them.

**श्री मोलू प्रसाद :** क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि जो लोग अर्न्तजातीय विवाह करें उनको सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उत्तर मंत्री महोदय ने नहीं दिया है।

**श्री रामबतार शास्त्री :** उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने कहा था कि सरकार ने डेवर कमिशन की नियुक्ति की थी और बहुत खर्चा करके उस कमिशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। बहुत अच्छी बातें उस रिपोर्ट में हैं। आखिर मैं जानना चाहता हूँ कि उस रिपोर्ट की जो कुछ अच्छी सिफारिशें हैं उनको लागू करने में सरकार के रास्ते में क्या कठिनाइयाँ हैं? इसका जवाब नहीं दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब दिलवाया जाए।

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** धर्म परिवर्तन की काफी यहाँ चर्चा हुई है। विदेशी मिशनरियों द्वारा लाखों लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उनकी मजबूरी का उनका गरीबी का लाभ उठाया गया है, उनकी बीमारी में उनको सहाता दे कर उनका धर्म परिवर्तन किया गया है। इसके बारे में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं कहा है।

एक सवाल लेकर समिति के बारे में भी उठाया गया है। उस रिपोर्ट के आधार पर बिल बनाने का जखरत था। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने पुनर्विचार करके कोई बिल बनाने का विचार किया है या नहीं किया है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने एक संसदीय समिति बनाने की बात भी कहा है जो राज्यों के अन्दर जा कर देख सके कि किस राज्य को कितना रुपया दिया गया है, किस राज्य ने क्या काम हरिजनों आदिवासी के कल्याण के लिए किया है और ठोक ढंग से इस काम को करवा सके। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप समिति बनाने को तैयार हैं?

**Shri Dhireswar Kalita (Gauhati):** I want to put just one question.

**Mr. Deputy-Speaker:** Now, no more questions. If I permit you, there are several others who want to put questions. Hon. Members should realise my difficulty. We have to take up another item now.

**Shri Dhireswar Kalita:** Sir, many hon. Members have raised the ques-

tion regarding extension of reservation. The hon. Minister has to reply to that.

**Mr. Deputy-Speaker:** He is going to take into consideration every suggestion made by hon. Members. The questions put now will also be considered and whatever is possible will be done. Hon. Members can write to him, communicate with him and talk to him. But this is not the way. I cannot continue the debate like this.

**श्री रामावतार शास्त्री :** जब आपने सवाल पूछने की इजाजत दी है तो जवाब भी दिलवाइये ।

**Mr. Deputy-Speaker:** If he begins to reply to the questions from Shri Swell onwards, it will take one more hour. It is not possible.

**Shri Dhireswar Kalita:** Sir, I rise to a point of order. If you allow questions to be put, you must also allow the Minister to reply.

**Mr. Deputy-Speaker:** As I said in the beginning, when Shri Swell put his questions and several others got up, the Minister will consider all the suggestions made. This is not a point of order. I cannot continue this debate like this.

I shall now put the amendments to the vote of the House. The first one is by Shri Frank Anthony.

The question is:

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

“but regrets the stultification of the guarantees given to the Anglo-Indian Community under article 333 of the Constitution.” (1)

*The motion was negatived.*

**Mr. Deputy-Speaker:** The next one is by Shri Siddayya. The question is:

That at the end of the motion, the

following be added, namely:—

“and is of opinion that a committee of Members of Parliament be constituted to keep a watch on the implementation of the recommendations of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes by the Central Government, State Governments and the Union territories.” (2)

*The motion was negatived.*

**Shri Siddayya:** Sir, I want to have a division on that amendment.

**Mr. Deputy-Speaker:** After the appeal of the Minister and announcement of appointment of a committee, I do not know what more you want.

**Shri Siddayya:** He has accepted my amendment in principle. Why does he not accept the amendment itself?

**Mr. Deputy-Speaker:** He has made an appeal accepting your suggestion. You did not also challenge my decision when the motion was negatived.

**Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara):** Sir, you are making a mistake. While voting is on you cannot canvass like this. It is not for the Chair to do. He has asked for a division.

**Mr. Deputy-Speaker:** Next is Shri Thakur's amendment. The question is:

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

“and places on record its general approval and acceptance of the recommendations contained therein and calls upon the Central Government, State Governments, Union territories and other administrative agencies to adopt them and to carry them out with determination and promptitude and is of opinion that a standing Parliamentary Committee be set up with full investigatory powers to look after the safeguards for the Scheduled Castes,



[Mr. Deputy-Speaker]

Scheduled Tribes and other Backward Classes." (3)

*The motion was negatived.*

**Mr. Deputy-Speaker:** I will now put the amendment of Shri Kansari Haldar to the vote of the House. The question is:

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"and is of opinion that the safeguards provided in the Constitution for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not being fully implemented."

*The Lok Sabha divided.*

**Division No. 17]**

**AYES**

**[15.57 hrs.]**

Adichan, Shri P. C.  
Amin, Shri Ramchandra J.  
Atam Das, Shri

Banerjee, Shri S. M.  
Basu, Shri Jyotirmoy  
Behera, Shri Baidhar  
Bhagaban Das, Shri  
Brij Bhushan Lal, Shri

Chandra Shekhar Singh,  
Shri  
Chittybabu, Shri C.  
Daschowdhury, Shri  
B. K.

Deiveekan, Shri  
Deo, Shri K. P.  
Singh  
Deo, Shri R. R. Singh  
Devgun, Shri Hardayal  
Dhirendranath, Shri

Dipa, Shri A.  
Dwivedy, Shri Suren-  
dranath

Fernandes, Shri  
George

Goel, Shri Shri Chand  
Gowda, Shri M. H.  
Gowder, Shri Nanja  
Gupta, Shri Indrajit

Haldar, Shri K.

Jena, Shri D. D.  
Jha, Shri S. C.  
Joshi, Shri Jagannath  
Rao  
Joshi, Shri S. M.

Kachwai, Shri Hukam  
Chand  
Kalita, Shri Dhireswar  
Kapoor, Shri Lakhan  
Lal  
Khan, Shri H. Ajmal  
Kirutinan, Shri  
Krishnamoorthi, Shri V.  
Kuchelar, Shri G.  
Kundu, Shri S.

Limaya, Shri Madhu

Madhok, Shri Bal Raj  
Madhukar, Shri K. M.  
Majhi, Shri M.  
Mangalathumadom, Shri  
Masani, Shri M. R.  
Mayavan, Shri  
Meetha Lal, Shri  
Meghachandra, Shri M.  
Menon, Shri Vishwa-  
natha  
Modak, Shri B. K.  
Mody, Shri Piloo  
Mohammad Ismail, Shri  
Mohammed Sheriff  
Shri

Molahu Prasad, Shri  
Mukerjee, Shri H. N.

Naik, Shri G. C.  
Nair, Shri N. Sreekantan  
Nair, Shri Vasudevan  
Nayar, Shri K. K.  
Nihal Singh, Shri

Pandey, Shri Sarjoo  
Patel, Shri J. H.  
Patil, Shri N. R.

Rajaram, Shri  
Ram Charan, Shri  
Ram Gopal, Shri  
Ramamvorthy, Shri P.  
Ramamurti, Shri P.  
Ramji Ram, Shri  
Ranga, Shri  
Ranjit Singh, Shri  
Ray, Shri Rabi  
Roy, Shri Chittaranjan

Sambhali, Shi Ishaq  
Sequeria, Shri  
Sharda Nand, Shri  
Shastri, Shri R.  
Shastri, Shri Raghuvir  
Singh  
Shastri, Shri Sheopujan  
Siddayya, Shri  
Singh, Shri J. B.  
Sivasankaran, Shri  
Somani, Shri N. K.  
Somasundaram, Shri  
S. D.  
Sondhi, Shri M. L.  
Subravelu, Shri  
Suraj Bhan, Shri

Tyagi, Shri O. P.

Vidyardhi, Shri R. S.  
Viswambharan, Shri P.  
Viswanathan, Shri G.

Xavier, Shri S.

Yadav, Shri Ram Sewak  
Yashpal Singh, Shri

NOES

Ahirwar, Shri Nathu Ram	Jadhav, Shri V. N.	Ram, Shri T.
Arumugam, Shri R. S.	Jaggaiiah, Shri K.	Ram Dhan, Shri
	Jagjiwan Ram, Shri	Ram Kishan, Shri
		Ram Sewak, Shri
Babunath Singh, Shri	Kamala Kumari, Shri-	Ram Subhag Singh, Dr.
Bajpai, Shri Shashibhu-	mati	Ram Swarup, Shri
shan	Katham, Shri B. N.	Randhir Singh, Shri
Bajpai, Shri Vidya Dhar	Kedaria, Shri C. M.	Rane, Shri
Barua, Shri R.	Khan, Shri M. A.	Rao, Shri Muthyal
Barupal, Shri P. L.	Kinder Lal, Shri	Reddi, Shri G. S.
Bhandare, Shri R. D.	Krishnan, Shri G. Y.	Reddy, Shri Surendar
	Kureel, Shri B. N.	Rohatgi, Shrimati Sush-
		la
		Roy, Shri Bishwanath
Chanda, Shri Anil K.	Laskar, Shri N. R.	
Chanda, Shrimati Jyot-		
sna	Mahadeva Prasad, Dr.	Sadhu Ram, Shri
Chaturvedi, Shri R. L.	Maharaj Singh, Shri	Saigal, Shri A. S.
Chaudhary, Shri Nitiraj	Mahida, Shri Narendra	Sanjit Rupji, Shri
Singh	Singh	Sankata Prasad, Dr.
Chavan, Shri Y. B.	Mehta, Shri Asoka	Sarma, Shri A. T.
	Mehta, Shri P. M.	Sayyad Ali, Shri
	Melkote, Dr.	Sen, Shri P. G.
Das, Shri N. T.	Menon, Shri Govinda	Shah, Shrimati Jayaben
Dass, Shri C.	Minimata, Shrimati	Shankaranand, Shri
Deoghare, Shri N. R.	Agam Dass Guru	Shastri, Shri B. N.
Desai, Shri Morarji	Mudrika Singh, Shri	Shastri, Shri Ramanand
Deshmukh, Shri B. D.		Sheo Narain, Shri
Dhillon, Shri G. S.		Shinkre, Shri
Digvijai Nath, Shri		Shiv Chandika Prasad,
	Oraon, Shri Kartik	Shri
Dixit, Shri G. C.		Supakar, Shri Sradha-
		kar
Gandhi, Shrimati Indira	Pahadia, Shri	
Ganesh, Shri K. R.	Panigrahi, Shri Chinta-	Tiwary, Shri K. N.
Ganpat Sahai, Shri	mani	
Ghosh, Shri Bimalkanti	Parmar, Shri Bihaljibha	
Girja Kumari, Shrimati	Partap Singh, Shri	Uikey, Shri M. G.
Gupta, Shri Ram Kishan	Patil, Shri A. V.	
	Patil, Shri Deorao	
Hazarika, Shri J. N.		Verma, Shri Balgovind
Himatsingka, Shri	Rajasekharan, Shri	Verma, Shri Prem
		Chand

16 hrs.

**Mr. Deputy-Speaker:** I would like to ascertain.....

**Some hon. Members:** No, no.

**Mr. Deputy-Speaker:** What happens is that though hon. Members press their buttons correctly, it is not recorded there or some hon. Members press it wrongly. Sometimes it

appears that after pressing the button some people... (Interruption). We will have to distribute slips.

**Some hon. Members:** No.

**Mr. Deputy-Speaker:** That is the only way. The result is not going to be changed. The machine is not working... (Interruption). If you want I will declare it.

**Some Hon. Members:** Yes.

**Mr. Deputy-Speaker:** Because it is not correct, I want it to be done again. But I declare it. "Ayes" have 91 and "Noes" have 89.

**The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh):** I challenge it.... (Interruptions).

**Mr. Deputy-Speaker:** It is not correct... (Interruption).

It has been challenged. I will distribute slips.... (Interruption). I have declared the count; I have not said anything about the motion. (Interruptions). It has been challenged. I will have to take vote a second time.

**Some hon. Members:** No, no. (Interruptions).

**Mr. Deputy-Speaker:** There is the procedure.... (Interruptions). I have not declared the result. Have I declared the result? (Interruption).

**Shri Surendranath Dwivedy:** It is a great responsibility on you. You cannot act like this.... (Interruptions)

**Some hon. Members:** The Lobby doors have been opened... (Interruptions).

**Mr. Deputy-Speaker:** I have not ordered the Lobby doors to be opened. The Lobby doors have not been opened. (Interruptions).

**Shri Madhu Limaye (Monghyr):** On a point of order, Sir.

**Mr. Deputy-Speaker:** There is a point of order. I will listen to him.

**Shri M. R. Masani (Rajkot):** Rule 367B(3) is quite clear. This particular sub-rule says:

"(c) The result of the Division shall be announced by the Speaker and it shall not be challenged."

There is no way of ordering a vote again so far as this motion is con-

cerned. The vote cannot be re-ordered.

**Mr. Deputy-Speaker:** I have not declared the result.

**Shri Surendranath Dwivedy:** You have declared the result. (Interruptions).

**श्री मधु लिमये :** मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप पहले मेरा बात सुनिए। कृपया नियम 367 (ए) का दूसरा हिस्सा पढ़िये ठीक तरह से :

Division by automatic vote recorder.

"After the result of the voting appears on the indicator board, the result of the Division shall be announced by the Speaker and it shall not be challenged."

अब डॉ० राम सुभग सिंह को कोई अधिकार नहीं है चुनौती देने का। अब यह लोक सभा का निर्णय है।

**Dr. Ram Subhag Singh:** I have got a right... (Interruption). The vote recorded by the automatic recorder must be accepted. (Interruption).

**Some hon. Members:** No, no.

**Shri Bal Raj Madhok:** This machine has not been working during the full session and whenever this machine gave the results votes of people have been ascertained by the employees of the Secretariat and that result has been declared. The same thing has been done today. You cannot change the practice just for their sake. The result is that the "Ayes" have won and the "Noes" have lost. Therefore, there can be no change in the result.

**Dr. Ram Subhag Singh:** It is quite clear that the result of the voting as appearing on the indicator board shall be announced by the Speaker "and it shall not be challenged". We accept that.

**श्री मधु लिमये :** आप ने जो घोषणा की है वह भाबीरी है।

**Mr. Deputy-Speaker:** I do not want to follow any procedure which is not laid down here.... (*Interruption*).

**Shri Surendranath Dwivedy:** The rule is very clear so far as it goes. If you read sub-rule (3) of rule 367A.....

**Shri K. K. Nayar (Bahraich):** How are people coming in?

**श्री मधु लिमये :** अब घंटियाँ हों गई,  
अब वह मेहरबानी करने जगह खाली करे।

**Shri Surendranath Dwivedy:** Rule 367A, sub-rule (3) clearly states:

"A Member who is not able to cast his vote by pressing the button provided for the purpose due to any reason considered sufficient by the Speaker, may, with the permission of the Speaker, have his vote recorded verbally by stating whether he is in favour of or against the motion, before the result of the Division is announced."

Then, sub-rule (4) says:

"If a Member finds that he has voted by mistake by pressing the wrong button, he may be allowed to correct his mistake, provided he brings it to the notice of the Speaker before the result of the Division is announced."

**श्री मधु लिमये :** अब डॉ. राम सुभग सिंह को छुट्टी दी जाय।

**Shri Surendranath Dwivedy:** It is very clear.

**Mr. Deputy-Speaker:** I have followed what you have said. Please resume your seat.

**Shri Surendranath Dwivedy:** Let us give a fair decision. What you have done is that after the votes were recorded on the indicator board you sent your men and all those who did not vote also recorded their votes in favour or against. After that, you announced the result. So, there is no question of anybody challenging it.... (*Interruptions*).

**श्री स० नो० बनर्जी (कानपुर) :** देखिए मरहटा में जो व्ज निकल चुकी थी वह पूरी होगी।

**Mr. Deputy-Speaker:** Do not bring in extraneous matters. Here we are concerned with this amendment.

**Shri K. K. Nayar:** After the division was over, you ordered the Secretariat staff to go round and record the votes of those Members who were not able to use the voting indicator because of its defect. You asked the staff to take down the Division Numbers of those affected. They did so and gave you the figures. You had thereafter confabulation with the Secretary for some time. On that, this side of the House because alarmed as we felt convinced that the amendment has been carried and the announcement of the result was being delayed because.... (*Interruptions*). You said that it appeared that some Members, who had already used the machine to record their votes, had again given their Division Numbers to the staff. We refuted that suggestion, which is also an insult to the House. We clamoured for the announcement of the result. In deference to that and possibly because....

**Mr. Deputy-Speaker:** Where is the necessity for all this argument? I have accepted it.... (*Interruptions*). What Shri Madhok and Shri Surendranath Dwivedy have said, I accepted it. So, please resume your seat.

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** यह सरकार इस्तफा दे।

**Dr. Ram Subhag Singh:** The votes that have been recorded, I have already challenged it. I said that it is a wrong figure.... (*Interruptions*).

**Shri Rajaram (Salem):** Sir, since you have announced the result....

**Mr. Deputy-Speaker:** We have had enough discussion. I will not permit any more discussion.

**Shri M. L. Sondhi** (New Delhi): The counting was done in some unorthodox way.

**Mr. Deputy-Speaker:** I accept your interpretation entirely. I have observed earlier that while recording there was some mistake, some *garbad*. I said it .... (*Interruptions*). I am accepting what he said. Then, I have declared the count and not the result.

**Shri Rajaram:** May I know the difference between 'count' and 'result'?

**Mr. Deputy-Speaker:** Let me conclude. This is what I have got to say.

**Shri Rajaram:** Sir, on a point of clarification. I want to know the difference between "counting" and "result". This is a prelude to what is going to happen during the Unlawful Activities Bill. This is the verdict of the country.

**Mr. Deputy-Speaker:** What I was saying was that I declared the count and not the result.... (*Interruptions*). The hon. Member mentioned the sequence of events. If you go on like that, there is no end to it.

**Dr. Ram Subhag Singh:** Sir, the result that you declared was not a correct one. I had challenged that in time. They had recorded their votes on the Indicator and then some of them again stood up and they voted twice.... (*Interruptions*). I challenge that. You count your heads and we are prepared to count our heads. (*Interruptions*).

**Mr. Deputy-Speaker:** I do not want to accept his argument. I want to declare the result because I have only declared the count. (*Interruptions*). You must recollect one thing that I did not want to change the count. Though I said that there was some *garbad*, I did not want to change it. I will declare the result. (*Interruptions*). Please resume your seats. I presumed, according to the Rules—I do not want to argue—that before the declaration of the result, there was

the chance of challenging it under the Rules. But now you cannot take advantage of that position.

Now, I declare that the Amendment is carried.

*The amendment was adopted.*

**Mr. Deputy-Speaker:** The motion, as amended, will have to be put to vote now.... (*Interruptions*). I will have to continue the process. I will have to put the motion, as amended, to the vote of the House. (*Interruptions*). I will not listen to anyone in the midst of this process. Please resume your seats. Shall I put it to vote?

**श्री मधु लिमये :** एक विनम्र निवेदन सुनिए। आपने कहा कि डोर्स आर बीईंग बलोज्ड। मैं अंग्रेजी जानता नहीं इस लिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उस समय वह दरवाजा खुला था ? .... (व्यवधान) ... हम को जरा शक हं रहा है।

**Mr. Deputy-Speaker:** When I am putting the motion to the vote, if any of you challenge the result, I have to clear the lobbies again.... (*Interruptions*).

**The Minister of Law (Shri Govinda Menon):** This is a second voting; it is a separate voting on a new question.

**Shri Surendranath Dwivedy:** If the lobby doors have been opened, then it will be wrong. We are in the process of voting. How can you again open the doors?

**Mr. Deputy-Speaker:** I have said so many times that the doors are closed. I am only asking you whether you are going to challenge the result of voting, in which case the doors are to be opened again.

**Some hon. Members:** No, no.

**श्री मधु लिमये :** यह कैसे, अध्यक्ष महोदय हो सकता है ; .... (व्यवधान) ... मैं तो जल्टा कर रहा हूँ। दरवाजा खुलना ही नहीं चाहिए।

**Mr. Deputy-Speaker:** Then, let me put the motion, as amended, before the House. The question is:

16.30 hrs.

[MR. SPEAKER in the Chair]

"That this House takes note of the Fourteenth and Fifteenth Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1964-65 and 1965-66, laid on the Table of the House on the 30th March, 1967 and 8th June, 1967, respectively, and is of opinion that the safeguards provided in the Constitution for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not being fully implemented."

**Shri Govinda Menon:** It is voting on a separate motion. It will be a new division.

**Shri Surendranath Dwivedy:** It is the original motion, as amended by the House.

**Shri Bal Raj Madhok:** As the amendment has been accepted, the motion as amended is put to the vote.

**Dr. Ram Subhag Singh:** It will be a separate voting.

**Mr. Deputy-Speaker:** If it is challenged.

**Dr. Ram Subhag Singh:** I am challenging it.

**Mr. Deputy-Speaker:** When it is put to the vote, you can challenge it. I am putting the amended motion to the vote of the House. The question is:

"That this House takes note of the Fourteenth and Fifteenth Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1964-65 and 1965-66, laid on the Table of the House on the 30th March, 1967 and 8th June, 1967, respectively, and is of opinion that the safeguards provided in the Constitution for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not being fully implemented."

**Mr. Speaker:** Let the doors be opened and let the lobbies be cleared.... (Interruption). Will you kindly sit now? I will request hon. Members to take their seats. May I request hon. Members to take their seats?

**Shri Surendranath Dwivedy:** Sir, we are in the process of voting. Already the motion is before the House. The Deputy-Speaker, who was in the Chair, asked for the "Ayes" and the "Noes". That has been recorded also. The division has been challenged. Previous to that, already voting has taken place. We specifically asked the Deputy-Speaker—he is present here—whether the doors would be opened or kept closed and he said that doors are not going to be opened. Now we are surprised that when you came you ordered the doors to be opened. Others are coming in. It is not fair.

**Shri Rajaram:** For a simple thing such a big government is doing it in a bad way. It is a bad precedent. It is a very bad thing for the Congress Party to do this. If they wanted to rule the country continuously, this is not the method. This is not the constitutional method.

**Dr. Ram Subhag Singh:** The hon. Deputy-Speaker had ordered for division and the votes were recorded on the indicator board. After the votes were recorded on the indicator board I challenged that some persons, who had got their votes recorded, were also standing up. But despite that challenge the division result was declared. Then we asked for a division again and the Deputy-Speaker ruled that the first declared result will stand. After that he has put the main motion, as amended, to the vote of the House. It is a completely new division. It has nothing to do with the process of voting that took place earlier.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, सब से पहले आपको एक बात का निर्णय करना है—जैसा कि नियमों में बताया गया है कि बहस समाप्त होने के पश्चात् . . .

अध्यक्ष महोदय : कौन सा कूल ?

श्री मधु लिमये : 367 है ।

"On the conclusion of a debate, the Speaker shall put the question...."

तो इस समय आपके सामने एक तरमीम थी, संशोधन था, जिसके ऊपर वोट लिये गये, उसका नतीजा घोषित किया गया—जिसको हम लोग जानते हैं . . .

डा० राम सुभग सिंह : नहीं किया गया ।

श्री मधु लिमये : अब आप स्पीकर साहब के निर्णय को चैलेन्ज नहीं कर सकते । स्पीकर ने निर्णय दिया है—उसको आप चैलेन्ज नहीं कर सकते हैं । जब विभाजन के बाद नतीजे की घोषणा होती है तो उसको चुनौती नहीं दे सकते—यह मामला तय हो गया है—अब उसको दोबारा न उठाइये । हमारे जो तरमीम है वह पास हो गई है, लेकिन मतदान की प्रक्रिया अभी भी अधूरी है । हम ने बार बार पूछा कि दर्वाजा बन्द है न । उन्होंने यही जवाब दिया कि—

Doors are being closed या doors have been closed ?

मुझे अंग्रेजी अच्छी तरह नहीं आती है, इसी लिये आशंका थी । लेकिन उन्होंने—अध्यक्ष महोदय ने यही कहा कि दर्वाजे बन्द हैं । आप रिकार्ड को देख लीजिये—उन्होंने यही कहा कि दर्वाजे बन्द हैं, खाले नहीं जायेंगे और जो संशोधित प्रस्ताव है, वह अब वोट के लिये रखा जायगा । लेकिन अब ये लोग नये लोगों को लेकर आये हैं, ऐसा हम को लगता है . . . व्यवधान . . .

पहले उसके बारे में सदन निश्चित हो जाय, तब आगे चला जाय ।

श्री बलराज मधोक : यह एक बड़ा संकट का विषय है जो इस समय हमारे सामने है : यहां पर सरकार की ओर से एक मोशन के ऊपर डिबेट चल रही थी । उस डिबेट में विपक्ष का संशोधन पास किया गया और जब वोटिंग हुआ तो उस संशोधन को स्वीकार कर लिया गया । अभी पार्लियामेन्ट्री मिनिस्टर की ओर से यह कहा गया कि यहां कुछ लोगों की ओर से गड़बड़ हुई है—मैं समझता हूं कि यह कहना कि वोटिंग में गड़बड़ हुई है या किसी ने गलत बात बतलाई है—It is a reflection on the whole House. (व्यवधान)

मेरी बात सुनिये । इस हाउस में जो मशीन है यह ठीक प्रकार से काम नहीं करती है, इस लिये हर बार जब मशीन से वोटिंग होती है तो जिनका वोट उस में दर्ज नहीं होता है उन के वोट को यहां के कर्मचारी उन से जा कर लेते हैं और हमेशा उस को स्वीकार किया जाता है । आज भी ऐसा ही किया गया । अब कोई यह कहे कि उस में गड़बड़ हुई है—मैं फिर से रिपीट करता हूं—

It is a reflection on the whole House. It must not be said. If he has said it, he must withdraw it.

इन लोगों को आपके कर्मचारियों पर विवास नहीं, हम लोगों पर विवास नहीं है । जो वोटिंग यहां पर हुआ है वह ठीक था, उस में गवर्नमेन्ट हारी है ।

अब यह जो मैं मोशन था—यह सारा एक ही विषय था, जब पहले वोटिंग के लिये दर्वाजा बन्द था तो उस को बन्द रखना चाहिये था । हम ने बार बार यहां पूछा कि क्या दर्वाजा बन्द है ? लेकिन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि दर्वाजा खोला गया और बहुत से सदस्य जो पहले यहां पर प्रेजेंट नहीं थे लाये गये । यह चीज गलत है । जो बाहर से लाये गये, उन को बाहर जाना चाहिये तब इस पर वोटिंग होना चाहिये ।

**Shri Surendra Nath Dwivedy:** We want to know whether the doors were opened at the request or order of the Chair. Who ordered that?

**Mr. Speaker:** He may please sit down. Mr. Madhok says that the Deputy-Speaker specifically said about the second voting. The first voting has been done. The result of the first voting has been announced; he has announced it as 91 and 89 or so. That was over the amendment. This is second voting.

**Shri Khadilkar (Khed):** When Shri Madhu Limaye asked me 'Are the doors closed?' I said 'They are closed'. That is true. After the first voting was finished, I had to put to vote the motion as amended. After voice vote was taken, it was challenged from the other side. Now, it is second voting. I have gone through the rule very carefully, and when it is a question of second vote, the lobbies have to be cleared for a second time. So, I ordered the Lobbies to be cleared. That is the position. (*Interruptions*).

**Mr. Speaker:** Now, it cannot be challenged. He has done it. There it ends.

Now, I shall put to vote the motion as amended.

The question is:

"That this House takes note of the Fourteenth and Fifteenth Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1964-65 and 1965-66, laid on the Table of the House on the 30th March, 1967 and 8th June, 1967 respectively, and is of opinion that the safeguards provided in the Constitution for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not being fully implemented."

Those who are for it may say 'Aye'.

**Some hon. Members:** Aye.

**Mr. Speaker:** Those who are against may say 'No'.

**Some hon. Members:** No.

1884 (A1) LSD—10.

**Mr. Speaker:** The 'Noes' have it....

**Shri Surendranath Dwivedy:** We challenge it. But may I submit that you cannot force a division like this?

**Mr. Speaker:** The Deputy-Speaker has clearly said that already.

**श्री मधु लिमये :** हम प्रापका निर्णय मानेंगे लेकिन किस नियम के मातहत यह है।

**Shri Surendranath Dwivedy:** On a previous occasion, when there were contradictory statements made, and the statement of the Chair was challenged, the records were brought. I would request you to bring the records to know clearly what the Deputy-Speaker had said.

**श्री मधु लिमये :** यह सदन नेता ने हमारे सामने—परम्परा रखी है, उन्होंने रास्ता बताया है।

**Mr. Speaker:** Anyway, he wanted to put it to vote.

What he has said can be seen later on and it can be looked into.

Shall I put it to vote again? That is the only procedure now.

**Some hon. Members:** There cannot be fresh voting again.

**Mr. Speaker:** He has clearly said that he had asked the Lobbies to be cleared. Therefore, I have put it to vote. Again, I shall put it to vote as amended.

The amendment is passed; that is accepted. Now, I have to put the motion, as amended, to the vote of the House.

The question is:

"That this House takes note of the Fourteenth and Fifteenth Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1964-65 and 1965-66, laid on the Table of the



[Mr. Speaker]

House on the 30th March, 1967 and 8th June, 1967, respectively and is of opinion that the safeguards provided in the Constitution for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not being fully implemented."

Let the Lobby be cleared.

**Shri Surendranath Dwivedy:** The report had already come that the Lobby had been cleared. In the meantime we were holding a discussion. The Lobby cannot be cleared again. It has already been cleared. We challenge you. How can it be cleared again?

**Shri Sezhiyan (Kubakonam):** For a second time it had been cleared and the doors had been closed after that. The doors cannot be opened again.

**Mr. Speaker:** Shall we have voting with slips now?

**Shri Surendranath Dwivedy:** We shall have automatic voting.

**Mr. Speaker:** All right.

*The Lok Sabha divided:*

**Shri Surendranath Dwivedy:** I find that a Member of the Rajya Sabha who has no vote here is going round and asking Members about voting. This is neither proper nor fair. Let us have slips.

**Mr. Speaker:** Is that the desire, that there should be slips?

Some hon. Members: Yes.

**Mr. Speaker:** After all, it is not as though anybody wants wrong voting. If a Member of the Rajya Sabha who is a Minister is present in the House during voting, it is not against rules. Only he cannot vote—that is all.

If you are challenging the figures, slips will have to be distributed.

**Shri P. Ramamurti (Madurai):** Yes, slips.

**Mr. Speaker:** I do not know what purpose it serves. I have no objection. It only means another half hour delay, nothing else.

**Shri Surendranath Dwivedy:** I suggest that you ask the 'Ayes' to rise in their places and take the count and then ask the 'Noes' to rise in their places and take the count.

**Mr. Speaker:** Will that satisfy?

Some hon. Members: Yes.

**Mr. Speaker:** Those who are in favour of the amended motion will please rise in their places—I find there are 107.

**Mr. Speaker:** Now, the hon. Members who are opposed to this motion may stand in their seats—The Noes are 115.

The motion, as amended, is negatived.

*The motion, as, amended was negatived.*

**Shri Shri Chand Goel (Chandigarh):** Sir, on a point of order... (*Interruptions*). I want to submit that it is the government motion, though in an amended form, which has been lost and if the government motion is lost, this government has no right to carry on the government of the country. This government should resign and quit because the government motion has fallen through.

**Mr. Speaker:** You cannot replace governments by points of order. It is almost 5 o'clock now. We will take up the next item.

16.53 hrs.

# UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) BILL

**The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan):** Sir, I move:

"That the Bill to provide for the more effective prevention of